

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवतरण

विशय सूची

सोमवार, 17 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
भाोक प्रस्ताव	(7)1
तारांकित प्र न एंव उत्तर	(7)2

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7)21
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)28
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(7)30
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण – श्री ओम प्रका ा चौटाला द्वारा	(7)44
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)45
सदस्य का नाम लेना	(7)48
वाक-आऊट	(7)49
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)49

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 17 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में दोपहर अपराहन 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने भाोक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े भाोक के साथ भाोक प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं। यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री मुख्तियार सिंह मलिक के 14 मार्च, 2008 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। उनका जन्म 3 जुलाई, 1911 को हुआ। उन्होंने दे आ के स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1980 से 1984 के दौरान हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम के अध्यक्ष रहे। 1967 और 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गए व 1971 एवं 1989 में लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने सदा आम आदमी के उत्थान के लिए कार्य किया। वे अनेक भौक्षिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। आज के दिन वे हमारे हरियाणा के सबसे सीनियर राजनीतिज्ञ थे। वे मेरे पिता जी से भी ज्यादा उम्र के थे। उनके निधन से दे आ एक अनुभवी सांसद एवं योग्य

प्र शासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो एक-एक करके हमें छोड़ कर जा रहे हैं। यह सदन जिला रिवाड़ी के गांव माजरा भयोरराज के स्वतंत्रता सेनानी श्री ओंकार सिंह के 9 मार्च, 2008 को हुए निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। उनके निधन से दे 1 एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से यह सदन जीन्दजिले के एक गांव इगरा के वीर सैनिक श्री सूबे सिंह के 6 मार्च, 2008 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। उनके निधन से दे 1 एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ. सु गील इन्दौरा (एस.सी. ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाोक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखे हैं, मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुए अपनी पार्टी तथा अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से गहरा भाोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगतों के भाोक संतप्त परिवारों के

सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि श्री मुख्तियार सिंह मलिक, श्री ओंकार सिंह तथा श्री सूबे सिंह के भाोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी से उबरने की भाकित प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री ने श्री मुख्तियार सिंह मलिक के निधन पर जो भाोक प्रस्ताव रखा है और डॉ. इन्दौरा ने उनके बारे में जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूँ। श्री मुख्तियार सिंह मलिक, दो बार लोक सभा में, दो बार राज्य सभा में तथा दो बार विधान सभा में चुन कर आये थे। वह एक प्रतिभा ाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी रूचि न केवल खेल कूद में तथा ि ाक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में थी बल्कि वह एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी थे। उनके निधन से हम सभी ने एक सच्चा समाज सेवी खो दिया है। श्री ओंकार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी तथा श्री सूबे सिंह, वीर सैनिक के निधन पर भी मुझे गहरा भाोक लगा है। श्री ओंकार सिंह ने अपनी जवानी के बहुमूल्य साल दे ा को अर्पित किए और सूबे सिंह ने दे ा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

मैं परमपिता परमात्मा से इन सभी दिवंगत आत्माओं को भांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और इन भाोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो

मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की भान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions hour.

Divider on circular Road, Bhiwani.

***873. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide divider on throughout the circular road of Bhiwani ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, The divider already stands provided in 3.05 km. out of a total length of 5.91 km. As regards the remaining portion, construction of divider will be taken up only after study of traffic movements and right of way.

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Sir, There is already a lot of congestion on the road in Bhiwani especially on circular road because there is no by-pass. It becomes quite dangerous in the morning hours and in the afternoon when the schools are over. the half of the portion of the road is having divider and half of the road is not having divider. At some places, the road needs to be widened. There is also a footpath. Somewhere it is 8 feet wide and somewhere it is 18 feet. I would request

the Hon'ble Minister that symmetry to the road be provided. It will help in removing the traffic congestion and it will avoid accidents. If the footpaths are also put into order in symmetry, the roads will also get widened.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के अन्दर 3.05 किलो मीटर के बीच में डिवाइडर प्रोवाइड किया गया है। रोहतक के गेट से देवसर गेट तक ऐसा ऐरिया है जहां पर ज्यादा भाँप्स वगैरा न होने के कारण कन्जै न नही है लेकिन हांसी गेट से घण्टा घर तक दोनों तरफ काफी दुकानें है। देवसर पहुंचने के बाद वहां पर काफी कन्जै न रहती है क्योंकि साईडों में सभी लोग वहां पर गाड़ियां खड़ी करते है जिसकी वजह से वहां पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विशेषतौर पर हांसी चौक से घण्टा घर 800 मीटर का ऐरिया ऐसा है जिसमें काफी ट्रैफिक कन्जै न है। मैं माननीय सदस्य से एक बात कह सकता हूं कि जो इनका ऐरिया है रोहतक गेट से हांसी गेट तक इसमें बस स्टैंड आता है और इसके दोनों तरफ आसपास के काफी दुकानें बनी हुई है। इसी प्रकार से घण्टा घर से देवसर गेट तक जो पोर न है जो कृष्णा चौक से होते हुए आता है यहां पर कई जगह भाँप्स है। स्पीकर सर, मैं इनसे इतना ही कह सकता हूं कि जहां-जहां दोनों तरफ भाँप्स न हों और इवन चाहे रैजिडेंसियल कॉलोनिज हैं इसको हम एग्जामिन करवाएंगे और जहां प्रोपर लगेगा वहां पर डिवाइडर बनवा देंगे। लेकिन जहां भाँपिंग कॉम्प्लैक्स है और यदि वहां पर कन्जै न है तो वहां पर

यह नहीं हो सकेगा। जो बैंक कॉलोनी है उसके आस पास ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है और वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती है जिसके कारण वहां पर लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Minister think about constructing a by-pass in Bhiwani to avoid traffic congestion ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बोर्ड-पास का सवाल है, उसके लिए माननीय सदस्य मुझे सैपरेट नोटिस दें। अभी पीछे भी एक क्वै चन आया था। उस ऐरिया में एक साईड से तो कुछ पोरान बना हुआ है और कुछ पोरान ऐसा है जो नहीं बन पाया है। इस पोरान को हम एग्जामिन करवा लेते हैं। इसमें कन्सल्टेंट से जांच करवा लेंगे और उसके बाद उसके ऐस्टिमेटस बनवा लेंगे और यह देख लेते हैं कि वह फिजिबल है या नहीं है। स्पीकर, दूसरी बात यह है कि उसको टोल से बनाए या सरकार के बजट से बनाएं, मैं यह सारा मामला देख कर ही इसके बारे में जवाब दे सकूंगा।

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कैथल-पेहवा चौक से करनाल बाई-पास बहुत ही चौड़ी सड़क है। यह मुख्य रोड हैं। उस सड़क के दोनों तरफ सरकारी कोर्ट्स हैं, रेस्ट हाऊसिंज है, रैजिडेंसियल ऐरिया और सरकारी दफ्तर भी है और वहां पर डी.

सी., एस.पी. के रैजिडेंस भी है। वहां पर कोई दुकान नहीं है। क्या मंत्री जी वहां पर डिवाइडर बनवाने का कश्ट करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से जो बात सदन में रखी है कि क्या कैथल-पेहवा चौक से करनाल बाईपास तक डिवाइडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि यह सरकार की तरफ से सैंकान है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को यह बताना चाहूंगा कि हम इस बारे में देख लेंगे और अगर यह सरकार की तरफ से मंजूर होगी या मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बारे में घोशणा की गई होगी तो सरकार जरूर इस बारे में कार्यवाही करेगी।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि यह जो सदन में डिवाइडर बनाने के बारे में बात की जा रही है तो मेरे यहां पर कौसली रेलवे स्टेन से कनीना तक जो रोड है, यह बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। उसका डिवाइडर जो बनाया गया था वह नाहड़ गांव में फटता है। इस डिवाइडर कनीना की तरफ चला जाता है। एक डिवाइडर नाहड़, कवाहड़, बड़गी होते हुए बहुझोलरी जाता है। यहां पर रोड बिल्कुल ही खत्म है। क्या मंत्री जी उस रोड को ठीक करवाएंगे ? इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौसली से मातनहेल तक रोड है, के बारे में आवासन दिया था, मंत्री जी उसको भी ठीक करवाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अनाऊंसमेंट की है तो उसको जरूर ठीक करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिवाइडर की बात की है तो मैं इस बारे में मैडम जी से कहूंगा कि हम इस बारे में चैक करवाएंगे कि वहां पर डिवाइडर बनाने से ज्यादा कन्जै इन न हो जाए इसके बारे में एग्जामिन करवाएंगे। इसके अलावा जो रोड़ की रिपेयर ही बात है, अगर वह टूटी हुई होगी तो हम उसको जरूर रिपेयर करवाएंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, डिवाइडर तो आलरेडी बना हुआ है उसको रिपेयर करने की बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में आ वासन दे दिया है कि अगर वह टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करवा देंगे।

श्री के.एल. भार्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 3.05 किलोमीटर पर डिवाइडर बन गया है लेकिन बाकी के डिवाइडर ट्रैफिक की मूवमेंट को देखकर ही बनाए जाएंगे। मेरा तो यह कहना है कि यह सड़क पहले ही ट्रैफिक की मूवमेंट को देखकर ही बनाई जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस जवाब का क्या मतलब है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रोहतक गेट से देवसर गेट का जो पोर इन है वह वाया दादरी गेट होते हुए

आता है, वहां पर रैजिडेंसियल ऐरिया ज्यादा है और भाँपिंग कॉम्पलैक्स कम है। यह उस वक्त बनाया गया था जब वहां पर भाँपिंग कॉम्पलैक्स वगैरह नहीं थे। जहां की ये मांग कर रहे हैं वहां पर बाजार है और इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर घंटा घर से हांसी गेट तक बहुत ही कन्जैशन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा था कि अगर वहां पर स्पेस अवेलेबल होगा, ट्रैफिक का कन्जैशन नहीं होगा तो हम वहां पर डिवाइडर बनवाएंगे। अब भिवानी में अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाए या कोई गाड़ी टेढ़ी कर दे तो वहां से सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में कन्जैशन के बारे में कहा है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि घंटा घर से हांसी चौक तक आलरेडी ही डिवाइडर है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही बताया है कि वहां पर डिवाइडरन है और उसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का कन्जैशन रहती है। अगर हम उस डिवाइडर को वहां से हटा देंगे तो वहां पर कुछ कन्जैशन कम हो सकती है। मैंने अपने जवाब में यही कहा था।

श्री के.एल. भार्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में जो कहा है इसमें यह कहना चाहिए था कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस की वजह से बनाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में यही कहा था लेकिन आप सुनते तो नहीं हैं। आप अपनी कमेंटरी भुरु कर देते हैं।

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी भीड़ की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि भिवानी में हांसी गेट के ऊपर जो जीपें सवारियां ढोती हैं वह बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर खड़ी रहती हैं इस कारण वहां पर छोटी-छोटी गाड़ियों को रोड़ पार करना मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए मंत्री जी कोई जगह निश्चित करवाएंगे, कोई पारमानेंट हल निकालेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं तो रोड़ की बात कर सकता हूँ।

श्री सोमवीर सिंह : मेरा सवाल भी रोड़ से संबंधित है। मैं भीड़ की ही बात कह रहा हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां पर इस प्रकार की कमियां पायी जाएंगी वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव का यही काम है कि वह इस तरह की कमियों को दूर करे। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जीपें न खड़ी हों।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मेवात में भी कोई डिवाइडर बन सकता है ?

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान जी, आप कौन सी लाईन से मेवात का डिवाइड करना चाहते हो ?

श्री साहिदा खान : स्पीकर सर, तावडू से फिरोजपुर झिरका, बलकली, पुन्हाना और सोहना रोड्स पर बहुत जाम रहता है। मंत्री जी को इन सड़कों के बारे में बाखूबी पता है क्योंकि मंत्री जी तो ढाई साल तक वहां की ग्रीवैसिंज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं इसलिए इनके ऊपर तो हमारा ज्यादा हक बनता है। स्पीकर सर, जो पटौदी रोड नूंह जाती है वहां पर सामने ही अनाज मंडी पड़ती है और वहां पर जो चौक है उसको पटौदी सोहना रोड चौक कहा जाता है। वहां पर दो-दो घंटे जाम लगा रहता है लोग इन जाम की जगह से वहां पर जूझते रहते हैं। इसी तरह से नूंह वाली घाटी के अंदर लोगों की दिक्कत रहती है और इसी प्रकार से फिरोजपुर झिरका के अंदर जाम रहता है। डिप्टी स्पीकर साहब भी यहां बैठे हुए हैं ये इस बारे में बता सकते हैं। स्पीकर सर, जब अलवर साईड में जाना होता है तो वहां पर दो-दो घंटे जाम लगता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने दिन में इस रोडज का काम हो जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जहां तक मेवात के बारे में सवाल है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेवात एरिया के बारे में मैंने इसको पहले भी बताया था कि अभी फिलहाल ही सरकार ने मेवात के लिए 586

करोड़ रुपये एन.सी.आर. से ऐप्रूव करवाए है। हमने होडल, नूंह, पटौदी-पटौदी रोड की वाईडनिंग और स्ट्रेंग्थनिंग ऐप्रूव करवायी है। इसी तरह से हम गुडगांव, नूंह, पलवल रोड की भी वाईडनिंग और स्ट्रेंग्थनिंग करवाएंगे। जहां-जहां पर बाजार के एरियाज में अगर डिवाइडर प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी वहां-वहां पर हम यह काम भी करवाएंगे। हमने एन.सी.आर. से 586 करोड़ रुपये ऐप्रूव करवाए है इसलिए हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं जिसके बाद वहा की रोडज पर कन्जै न में कमी होगी।

Land Acquired by HUDA for Residential Sectors at Dadri

***939. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the Chief Minister be pleased to State the latest compensation table for land acquired by HUDA for residential sectors in Dadri together with the time by which the plots are likely to be made available for construction of residential buildings ?

Power Minister (Shir Randeep Singh Surjewala) : Sir, the rate of compensation for the land under acquisition for Sector 8 & 9 Part Dadri cannot be informed at this stage since the land has not yet been acquired. Notification under Section 6 of the Land Acquisition Act 1894 was issued for 154.50 acres on 20.2.2008. It is not possible to give the time by which the plots will be available for construction of residential buildings. Possession will be handed over after development works have been completed. अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं इसके साथ माननीय सदस्य की जानकारी के लिए जोड़ना चाहता हूं कि जहां तक जमीनों का मुआवजा है, क्योंकि

अभी जमीन ऐक्वायर नहीं हुई है, इसलिए इसका हम रेट अभी नहीं बता सकते। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की सरकार ने जमीनों के मुआवजे के बारे में मार्च, 2005 के अंदर लिया था और फिर इसके बाद मुआवजे में और बढ़ोत्तरी की थी। स्पीकर सर, हरियाणा पहला ऐसा प्रान्त है जहां पर फ्लोर रेट की पोलिसी जमीन के अधिग्रहण को लेकर है। इसके मुताबिक ही इस समय जमीन की लोके ान के मुताबिक 8 लाख रूपये, 16 लाख रूपये और 20 लाख रूपये प्रति एकड़ मुआवजा किसान को मिलता है। फाईनली जब किसान को पेमेंट मिलती है तो तीन प्रति ान सोले ि ायम मिलाकर ब्याज के साथ उसको पेमेंट मिलती है। यह अपने आप में एक अनूठी नीति है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो निर्णय किया है वह यह है कि जहां भूमि अधिग्रहण होगी, जो कि पूरे दे ा में नहीं है और भारत सरकार जो इस बारे में अपनी नीति बना रही है उसके अंदर भी इसे डालने पर विचार कर रही है जिस नीति को हमने लागू किया है। इस नीति में किसान को 15 हजार रूपये प्रति एकड़ जमीन के कम्पनसे ान के अलावा 33 साल तक मिलेंगे और इसमें हर साल 500 रूपये की बढ़ोत्तरी देने वाला हरियाणा अकेला प्रान्त है। (इस समय मेजे ं थपथपाई गई।)

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी दादरी

वाली जो जमीन है यह 8 लाख रूपये वाले स्लैब में आएगी या 16 लाख और 20 लाख रूपये वाले स्लैब में आएगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात लोके ान बेस्ड है। जैसा मैंने बताया कि जो चंडीगढ़ के साथ का क्षेत्र है उसका एक रेट है और जो गुड़गाव और एन.सी.आर. का इलाका है उसकी दूसरी स्लैब और बाकी हरियाणा की एक और स्लैब है। 8 लाख रूपये वाली स्लैब में दादरी का एरिया आएगा। इसमें 10 लाख 40 हजार रूपये के करीब सौले ि ायम व ब्याज के साथ मिलेगा। सैक ान 4 की नोटीफिके ान की डेट से जब तक भूमि की पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक 12 प्रति ात की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 15 हजार रूपये प्रति एकड़ की रा ि ा 33 साल तक और उस रा ि ा पर 500 रूपये की बढ़ोत्तरी हर साल मिलेगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसान जो जमीन का मालिक है वह यदि आव यक समझे कि मुआवजा उचित नहीं है तो वह कोर्ट में इन्हांसमेंट के लिए भी जा सकता है। यदि कोई लोके ान ऐसी है कि जहां कीमत ज्यादा है तो वे इन्हांसमेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। यह तो मैंने पलोर रेट बताया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय मेजर साहब ने जो सवाल उठाया था उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो हमारे सिपाही आते हैं, फौजी देना की सेवा करके वापस आते हैं। उन्हें प्लॉट आरक्षित करके दिए जाएंगे। माननीय सदस्य ने उनके बारे में जानना चाहा था कि अब तक सारे सैक्टर जनरल कैटेगरी के हैं, क्या कोई सैक्टर डिफेंस सर्विसेज के लिए बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्णय ले लिया है और पहला सैक्टर डिफेंस सर्विसेज के लिए ही बनाने जा रहे हैं।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर आज की तारीख में कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। अथोराइज्ड प्लॉट कोई नहीं है। अनअथोराइज्ड प्लॉट लेने पड़ते हैं। आज की तारीखमें दादरी सबसे बड़ा सब डिवीजन है। दो हजार के करीब प्लॉट हमें हमारे सिविलियन भाइयों के लिए चाहिए और तकरीबन एक हजार प्लॉट हमें रिटायर्ड और सर्विंग डिफेंस पर्सोनल के लिए चाहिए। 100 एकड़ भूमि हुडा अधिग्रहित करता है उसमें करीब 550 प्लॉट के करीब उपलब्ध होते हैं। 150 एकड़ कुल भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इसमें तकरीबन 750 प्लॉट चाहिए। हमारी डैफिनिट 2000 प्लॉट्स की है अगर हम

जल्द से जल्द बनाएं तो भी हमें एक और सैक्टर बहुत ही जरूरी चाहिए। दादरी में दस सैक्टर जिसको कि डिफेंस सैक्टर के लिए अधिग्रहित करने की योजना थी, उसके बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारि । करता हूं कि इसको डिफेंस सैक्टर के लिए ही बनाया जाए। 250 एकड़ जमीन से कम में हमारी पूर्ति नहीं होने वाली। आज की तारीख में 3 हजार से 4 हजार अनअथोराइज्ड प्लॉट खरीदने पड़ते हैं।

Mr. Speaker : You should ask the specific questions.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : सर, स्पेसिफिक क्वे चन यही है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसके अतिरिक्त डिफेंस के अलावा एक और सैक्टर बनाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्र न किया है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए डिफेंस पर्सोनल के लिए प्लॉट काटने की मांग उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उदार हृदय है उन्होंने कहा कि दादरी और भिवानी क्षेत्र में फौज के सिपाही ज्यादा हैं जो दे । की सेवा में वि ोश योगदान देते हैं इसलिए सरकार ने उनके लिए एक अलग से सैक्टर काटने का फैसला किया है। इसके लिए हम माननीय सदस्य से कम से कम धन्यवाद की अपेक्षा जरूर रखते हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सैक्टर 8

और 9 पार्ट का जिक्र किया है इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस सैक्टरों के लिए 154.50 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हम पहले फौजी सिपाहियों के लिए सैक्टर 8 बनायेंगे और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बाद में सैक्टर बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 151.15 एकड़ भूमि ऐक्वायर करने का फैसला किया है जिसमें सैक्टर 9 और सैक्टर 10 का पार्ट बनाएंगे। पहले 8 और 9 सैक्टर की जो दरखास्त आयेंगी उसमें देख लेंगे कितने प्लॉट दिए जायेंगे उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि सरकार ने जमीन को आईडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए पहले सैक्टर के लिए दरखास्त का रिस्पॉंस देखकर ही दूसरी जमीन लेने के लिए जल्द ही कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने घोषण कि है कि जिन किसानों की जमीन ऐक्वायर हुई है उनको 33 साल तक सरकार 15 हजार रूपये प्रति एकड़ हर साल मुआवजा देगी और हर साल 500 रूपये भी बढ़ायेगी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो हुडा ने प्लॉट अलॉट किए है क्या 33 साल तक उन अलॉटिज से भी सरकार इन्हांसमेंट का पैसा लेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्र न पूछा है उसके बारे में मैं उनको बताना

चाहूंगा कि जब सरकार उस जमीन का मूल्य आंकेगी तभी उसमें सारा मूल्य भामिल कर लिया जाएगा। यह नहीं कि 33 साल तक अलॉटिज से पैसा लेते रहेंगे। सरकार की मन् ता यह नहीं है। कम्पैन्से तन निर्धारित करते समय ही यह कीमत तय कर दी जायेगी और अलॉटी को इस एसैसमेंट से ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए यह सही नहीं है कि 33 साल तक अलॉटिज से कोई पैसा इन्हांसमेंट के रूप में लिया जायेगा।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, कोसली में 12-15 साल पहले हुडा द्वारा 10-15 एकड़ जमीन में सैक्टर के लिए प्लॉट काटे गए थे। इसमें समस्या यह है कि अनाज मण्डी की जमीन भी हुडज़ सैक्टर के साथ लगती है। अनाज मण्डी वाले यह कहते हैं कि जब तक हुडा के सैक्टर वाली जमीन से हमारी जमीन अलग नहीं होगी तो हम बूथ अलॉट कर सकते और हुडा सैक्टर वाले यह कहते हैं कि जब तक अनाज मण्डी के साथ लगती हमारी जमीन क्लीयर नहीं होती तब तक हम प्लॉट नहीं काट सकते। आम लोगों ने तो 10-15 साल पहले ही अपने पैसे प्लॉट और बूथ के लिए भर दिए थे लेकिन अब तक उनको न तो प्लॉट और बूथ मिल है और न ही उनका पैसा मिला है। यह पचरा बहुत दिन से लटका हुआ है। इस बारे में मैं मार्केटिंग कमेटी के ऑफिस में भी गई थी लेकिन आज तक यह मामला सुलझा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उन लोगों को

कब तक हुडा के प्लॉट मिल जायेंगे और व्यापारियों को ये बूथ कब तक अलॉट हो जायेंगे ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्र न किया है वह ही मुझे इस बारे में लिखकर भिजवा दें । मैं कल दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मामले का निपटारा करवा दूंगा ।

श्री नरे । यादव : स्पीर सर, एन.सी.आर. का दायरा बढ़ाया गया था और उस लिस्ट में अटेली का नाम भी दर्शाया गया था । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अटेली भाहर भी एन.सी.आर. में पड़ता है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्र न मूल प्र न से अलग है ।

आई.जी. भोरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हुडा सैक्टर के नाम पर जुलाना में वर्ष 2004 में प्लॉटों के लिए लोगों से दो-दो हजार या तीन-तीन हजार रुपये इकट्ठे किए गए थे और इस प्रकार से एक करोड़ रुपये के लगभग रूपया इकट्ठा किया गया था । क्योंकि मेरे पास इस बारे में रसीदें भी हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में पहले भी प्र न पूछ चुके हैं ।

आई.जी. भोरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बारे में रसीदें हैं और हुडा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई सैक्टर जुलाना में नहीं काटा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बारे में जांच करवायेंगे कि वह पैसा कहां गया ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय आई.जी. साहब ने पहले भी इस बारे में प्रश्न पूछा था और इस बारे में उनको जानकारी दे दी गई थी। 20 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसा लिया गया था, मैंने उस दिन भी इनको इस सदन में सरकार की तरफ से आवासन दिया था कि यह सारा पैसा हम अगले 3 महीने के अंदर 5 परसेंट ब्याज के साथ वापिस करेंगे।

डॉ. विठ्ठल भांकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में भी अनअथोराइज्ड कॉलोनीज की प्रोब्लम है। पिछले 14 मार्च को कुछ भारारती तत्वों ने वहां पर उपद्रव किया, वहां पर एक न्यू डिफेंस कॉलोनी है जहां अधिकतर डिफेंस सर्विसिज से आए हुए लोग रहते हैं और एक बैंक कॉलोनी है वहां 15-20 सालों से मकान बने हुए हैं, वहां सड़कें बनी हुई हैं, बिजली के खम्भे लगे हुए हैं लेकिन टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उन कॉलोनीज को गिराने के लिए जब पीला पंजा जाता है तो लोग भड़क जाते हैं और काफी उपद्रव हो जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूँ कि क्या इन दोनों कॉलोनियों को रैगुलर करने का सरकार का कोई प्रावधान है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भिवानी का सवाल है तो इस सरकार का बने हुए मकानों को गिराने का कोई इरादा नहीं है, यह केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, सरकार उनको ऐसे कब्जे नहीं करने देगी। इसलिए सरकार का साफ फ़ैसला है कि बने हुए मकानों को नहीं गिराया जाएगा।

श्री राधे भयाम भार्मा अमर : मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा नारनौल के अंदर हुड्डा के 9 सैक्टर डिवैल्प किए जा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है। नारनौल में भी बहुत अधिक संख्या में दे 1 की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन सैक्टरों में से एक सैक्टर इन सैनिकों के लिए भी रिजर्व करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी लिखवाकर मुख्यमंत्री महोदय को भिजवा दें क्योंकि इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय जी का रवैया हमें 11 सकारात्मक है। सरकार सर्वे करवाकर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार नारनौल में हुड्डा का एक सैक्टर बनाने बारे सवाल किया था तो

इन्होंने लिखित में जवाब दिया था कि 'नहीं' फिर इन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा था कि हमारे यहां एक सैक्टर जरूर बनाएंगे जो कि रिकॉर्ड की बात है तो बाद में जब मैंने इस बारे में पूछा तो ये कहने लगे कि आपके यहां सैक्टर बनाने की हमारी कोई प्रपोजल नहीं है। जहां सी क्लास कमेटियां बनी हुई है वहां सरकार की तरफ से इनको खाली करने के लिए बार-बार नोटिस जाते हैं। जहां ये सी क्लास कमेटियां बनी हुई हैं वहां न कोई सीवरेज की सुविधा है और न ही कोई दूसरी सुविधाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है और जहां सैक्टर नहीं बने हुए हैं वहां यह कानून लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग कहीं न कहीं तो बसेंगे और कहीं न कहीं तो प्लाट कटेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और उनको मालूम भी है कि इन्होंने पिछले सदन में भी एक मांग रखी थी और उससे पिछले सदन में भी इन्होंने एक मांग की थी कि नारनौंद में बस स्टैण्ड बनाया जाए तो मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी मंजूरी दे दी है और उसके लिए काफी रूपया भी दे दिया है और पिछले सत्र में इन्होंने मांग की थी कि नारनौंद में सीवरेज व्यवस्था करवाई जाए तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी

भी मंजूरी दे दी है और पैसा भी दे दिया गया है और काम भुरु हो गया है।

श्री रामकिान फौजी : अध्यक्ष महोदय, हमारा भिवानी नगरपालिका क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार का हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए भी कोई हुडा का सैक्टर बनाने का कोई प्रपोजल है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आज के दिन ऐसा कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है परन्तु मैं माननीय साथ को कहूंगा कि सफीं टायंट नम्बर ऑफ एम्प्लीकैट्स अगर तैयार हों तो मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कहा हुआ है कि हमारा मन खुला है हम वहां हुडा का सैक्टर काटेंगे इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि सफीं टायंट नम्बर ऑफ एम्प्लीकैट्स का समूह इकट्ठा करके उनकी रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री महोदय को दिलवा दें, उसके बाद उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी घोशणा की है कि जिनके मकान बने हैं उनके मकान नहीं गिराये जायेंगे। इसके साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कैथल भाहर में 2-3 हुडा के सैक्टर बने हुए हैं जिनमें कुछ गरीब आदमियों के छोटे-छोट मकान भी बने हुए हैं,

क्या मुख्यमंत्री जी उनको भी रैगूलराईज करने का आवासन देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने on the floor of the House स्पष्ट घोशणा की है कि जिन गरीब, आम और साधारण लोगों ने सैक्टर के अंदर मकान बना रखे हैं और वे मकान हुडा के सैक्टर की प्लानिंग में कोई मेजर रूकावट नहीं डाल रहे होंगे तो उन मकानों को नहीं गिराया जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला जी को मालूम है कि कैथल में कितने ज्यादा मकान छोड़े गये हैं, उसके लिए इन्हें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो मकान बिल्कुल नाजायज बने हुए हैं वह एक विचार करने की बात है। जो मकान सैक्टर 4 से पहले के बने हुए हैं वे मकान नहीं गिराये जायेंगे और जो मकान जमीन अधिग्रहण के बाद बने हैं और इललीगल हैं वे मकान गिराये जायेंगे।

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बावल में सबसे पहला गोथ सेंटर बना हुआ है लेकिन वहां पर आज तक हुडा का कोई सैक्टर नहीं है। क्या सरकार की बावल में हुडा का कोई सैक्टर बनाने की प्रपोजल विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का पृथक प्र न है। इस बारे में माननीय सदस्या लिखित में अलग से जवाब मांग लें, हम लिखित में उनके पास जवाब भिजवा देंगे।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोशणा की है कि जो मकान बने हुए हैं वे नहीं गिराये जायेंगे। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मकान नहीं गिराये जाने का क्या क्राईटेरिया है। बहुत सालों से जो मकान बने हुए हैं क्या उनको नहीं गिराया जाएगा? गुड़गांव के चक्करपुर गांव में 40 साल से लोगों ने मकान बना रखे हैं लेकिन अभी दो दिन पहले वहां पर लोगों को नोटिस मिला है कि उनके मकान गिराये जायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मकान गिराये जाने और न गिराये जाने के बारे में बड़े स्पष्ट तौर से, खुले मन से, स्पष्ट नीयत और नीति से सदन में घोशणा कर दी है। मुझे लगता है कि उसको बार-बार दोहराना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो मकान उस जमीन पर धारा-4 लगने से पहले के बने हुए हैं वे मकान अगर सैक्टर की प्लानिंग के अंदर मेजर आब्सट्रैक्सन नहीं करते, जिनमें थोड़ी बहुत गुंजाइ है और इधर-उधर से सड़क निकल सकती है तो वे मकान नहीं गिराये जायेंगे। यह सरकार का वायदा है। किसी एक जगह के बारे में

हम floor of the House आ वासन नहीं दे सकते। माननीय साथी ने जिस गांव का जिक्र किया है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें उसको एग्जामिन करवाकर हम कोई पोजीटिव हल निकाल लेंगे।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, जिन मकानों को बने हुए 40 साल हो गये उनको भी तोड़ने के लिए नीचे के लैवल पर नोटिस दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोशाणा कर दी है तो उनको नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस नीति का यह मतलब नहीं है कि प्रान्त के अन्दर अन रैगुलेटिड डिवैल्पमेंट भुरू हो जाये। जो नीति सरकार ने बनाई है उसका मतलब यह है कि यदि किसी आम, साधारण और गरीब आदमी ने किसी समय में अन प्लान एरिया में मकान बना लिया है और उसे बने हुए वर्षों बीत गये हैं। इस प्रकार के बने हुए मकानों को सरकार नहीं गिरायेगी। मैं मेरे माननीय साथी को एक बात और बताना चाहूंगा कि यह सही बात है कि जनता के हक में फैसला लेना सरकार का फर्ज होता है। हमारे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने उदार हृदय से इस प्रकार की उदार नीति लोगों के हित को ध्यान में रखकर लागू की है। पिछली सरकार के समय में गुडगांव के अलावा दूसरे भाहरों में भी सिलैक्टिव तरीके से लोगों के मकान डिमोलि । किए जाते थे। इस प्रकार का काम जो लोग सरकार के पक्षधर थे

वे करवाते थे। इस तरह की मं 11 उस समय की सरकार के पक्षधर लोगों की थी और गुडगांव के अन्दर भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया है कि पिछली सरकार द्वारा बहत सारे नोटिससिज जारी करके गुडगांव और दूसरे भाहरों के अन्दर बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज को रैगूलराईज किया गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है It would have to be decided on a case to case basis. Our intention is not to demolish anybody's house, our intention is, if somebody has constructed a house, we must try and adjust it within our planning. unless and until it comes within sector roads or some such facilities where it is impossible them we wiill have to take that away, otherwise we will do so, Sir, सैक्टर 4 लागू होने से पहले की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आपके जो स्पैसिफिक सुझाव है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें, हम उस केस की जानकारी पता करके पूरे तथ्यों के अनुसार पॉजीटिव तरीके से आपको सूचित करेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल दादरी से भुरू होकर पूरे हरियाणा में फैल गया है। इससे यह जाहिर होता है कि यह समस्या सारे हरियाणा की है। मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी ने इसके समाधान के लिए जवाब भी दिए हैं जो कि काबिले तारीफ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सारे हरियाणा की इसलिए है कि हम बढ़ती हुई आबादी और दूसरी जरूरतों के मुताबिक पहले ही से वहां पर सैक्टरज के लिए व्यवस्था नहीं करते। अगर हम पहले से

ही ऐसा करते तो आज जो इतनी अनवांटिड कॉलोनीज की ग्रोथ हो रही है तकरीबन उन भाहरों में खास तौर से बड़े कस्बों में और फरीदाबाद भी उसका एक हिस्सा है तो मैं एक बात आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि 70-80 परसेंट तक ये अनअर्थोराइज्ड कॉलोनीज बन गई है। ये अनअर्थोराइज्ड कॉलोनियां इसलिए बनी क्योंकि वहां पर सरकारी स्तर पर कोई अर्थोराइज्ड सैक्टर नहीं बन पाया और अर्थोराइज्ड सैक्टर न बनने की वजह से अनअर्थोराइज्ड कॉलोनीज डिवैल्प हो गई। जहां 70-80 परसेंट चाहे वह सारे हरियाणा में कहीं भी हो ये डिवैल्पमेंट हो गई है एक तो उनको अर्थोराइज्ड किया जाये और दूसरे सैक्टर बनाकर उस भाहर की सूरत बिगाड़े इसके लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाये। इसके अलावा सारे हरियाणा में एक सर्वे करवाया जाये कि जहां-जहां जिन कस्बों में, कमेटीज में और बड़े भाहरों में जहां आव यकता है उसके मुताबिक हम पहले ही या तो जमीन एक्वायर करें और या फिर प्राईवेट सैक्टर को उसके लिए इजाजत दें जिससे कि यह अनवांटिड ग्रोथ रूक सके और इस समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह वाजिब है। इससे सम्बन्धित पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं क्योंकि यह मसला इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने से पहले

जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना था तो उससे पहले बड़ी हड़बड़ी में एक ऑर्डर के तहत बहुत से सैक्टर और कॉलोनियों को रैगूलराईज किया गया। परन्तु जब मौजूदा सरकार ने कार्यभार सम्भाला अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सैक्टरों की संख्या में वह कॉलोनीज है जो कि अन अथोराईज्ड थी। जो बन गई थी और जिनके अन्दर कोई सुविधा नहीं थी। परन्तु फिर सरकार ने उन सबको रैगूलराईज करने का निर्णय लिया। हमने पानी, सीवरेज और सड़के इस प्रकार की तमाम सुविधायें वहां पर उपलब्ध करवाईं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हुडा का प्र न है तो हुडा अब तक 26 अलग-अलग भाहरों में 190 सैक्टर डिवैल्प कर चुका है और इसके तहत 2 लाख 49 हजार 98 प्लाट्स काटे जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आज के दिन जहां पर हुडा अर्बन एस्टेट बनाने जा रहा है उनमें नारायणगढ़, भाहबाद, गोहाना, हांसी, पटौदी, अग्रोहा, सफीदों, तरावड़ी, पेहवा और महेन्द्रगढ़ शामिल है। इन सभी भाहरों के अन्दर हम हुडा की अर्बन एस्टेट बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भी यह जरूरी लगेगा, जैसा कि मैंने बताया, आखिर में हुडा द्वारा वहां पर ही सैक्टर डिवैल्प किये जायेंगे, जहां पर सफी इंट मांग होगी। माननीय सदस्य को और भी जहां पर यह नजर आता है कि वहां पर हुडा सैक्टर डिवैल्प करे तो ये हमें बतायें वहां मांग के मुताबिक हुडा द्वारा सैक्टर डिवैल्प किये जायेंगे। हुडा इस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगा। जहां तक प्राईवेट लाइसेंसिज की बात है, प्राईवेट कॉलोनाईजर्स की बात है, तो सरकार ने इस बारे

में भी जो छोटे कस्बे और भाहर है वहां पर उदार हृदय से यह नीति बनाई है कि अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है और अगर आप सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे और उनको भाहरों की सुविधाओं से लिंकेजिज देंगे तो वह भी हम परमिट करते हैं। जैसे-जैसे दरखास्त आती है उनको मैरिट के आधार पर कंसीडर किया जाता है।

Status of Minicipal Committee to Nangal Chaudhary

***933. Sh. Naresh Yadav :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of Municipal Committee of Nangal Chaudhary ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : No, Sir.

श्री नरे । यादव : अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी जो कि नई कंस्टीच्यूसी बनी है। राजस्थान जाने वाले हाई.वे से जुड़े होने के कारण अटेली तथा नांगल चौधरी में आबादी लगभग बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि नांगल चौधरी में चारों तरफ से क्रै ार, रोड़ी और पत्थर लेने के लिए पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। यहां पर सड़कें भी टूटी पड़ी है और बस अड्डा भी नहीं है। यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने की भी बहुत जरूरत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको म्यूनिसिपल कमेटी बना दिया जाये तो हमारा उद्धार हो सकता है।

श्री ए.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी कस्बे को म्यूनिसिपल में कंवर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी तय की गई है और उस लिहाज से हमारे पास सिर्फ एक बार एक रिप्रेजेंटे अन आई थी जिसको अपने तौर तरीके से हमने जिला कलैक्टर से जानकारी हासिल करनी चाही उसके बारे में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कभी आई तो सरकार कभी भी ना नहीं करेगी। लेकिन सच यह है कि जो बड़े कस्बे म्यूनिसिपल में कंवर्ट हो करके नये नाम एक्वायर करना चाहते है वे न तो घर के रहते है और न ही घाट के। जो विकास के बारे में विभाग की गांवों के उत्थान की स्कीम है उनका भी फायदा नहीं उठा पायेंगे और दूसरी तरफ उनके पास साधन भी नहीं है। जैसे साथी नरे । यादव जी कह रहे है, बस अड्डा भी नहीं है, सड़के भी नहीं है। उनके पास बजट भी नहीं है। उनके पास रैवेन्यू के सोर्सिज भी नहीं है। तो वह न केवल सरकार के लिए बल्कि माननीय प्रतिनिधि के लिए भी सिरदर्दी बन जायेगी। मैं चाहूंगा कि इस मामले में वे जरूरत के आधार पर कोई बात कहेगें तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि उसे रैवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सरकार अमेंडमेंट 74 के तहत बाऊंड नहीं है कि एक पर्टीकुलर आबादी के लिए एक म्यूनिसिपल कमेटी जरूर बनाई जाए। दूसरे जो म्यूनिसिपल कमेटी आपके रिवाईज

की हैं उसके बावजूद वहां पर 20-20 हजार की आबादी वाले इलाके आपने छोड़ दिये हैं। उदाहरण के तौर पर हसनपुर ओर पुन्हाना को आप छोड़ रहे हैं। आखिर किस बिनाह पर छोड़ा गया है कोई तो क्राईटेरिया होगा ? वैसे क्राईटेरिया नहीं भी है तो भी सरकार संविधान सं. 10 धन 74 के तहत म्यूनिसिपल कमेटी बनाने के लिए बाऊंड है उनको तो आपको बनाना ही चाहिए।

श्री ए.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात स्पष्ट भावों में कही है कि किसी भाहर को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा देने के लिए क्राईटेरिया फिक्स है। 50 हजार से नीचे वाले भाहरों में म्यूनिसिपल कमेटी होगा, 50 हजार से 3 लाख के बीच की आबादी के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होगी और दूसरी अब गुड़गांव में बनने जा रही है। जहां तक सरकार का बाऊंड होने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझ पाया कि माननीय श्री गाबा साहब किस कानून का हवाला दे रहे हैं जो हमें बाऊंड करता है। दूसरे अगर म्यूनिसिपल कमेटी बना भी दी जाये तो इस बात का तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमें कितनी चुंगी चौकियां बनानी होंगी, कितने स्टाफ की भर्ती करनी होगी। कमेटी का ऑफिस किस प्रकार से लांच करना होगा और कम से कम स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा कमेटी से निकाला जाये। महज लॉयबलिटी लेकर अपने तौर पर कहीं पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, हसनपुर कस्बे में बहुत पुरानी नगरपालिका थी जो पिछली सरकार ने द्वेशपूर्ण नीति के कारण भंग कर दी थी। उसके बाद जो दूसरी नगरपालिकाएं भंग की गई थीं उनमें से 8-9 नगरपालिकाएं तो बहाल कर दी गई थीं लेकिन हसनपुर की नगरपालिका बहाल नहीं की गई थी। वहां पर अनाज मण्डी है, ब्लॉक भी है, पुलिस स्टेशन भी है, वहां पर कॉलेज भी है। इस तरह से हसनपुर नगरपालिका बनाए जाने के सारे नॉर्म्स पूरे करता है और उसके लिए सरकार को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने अन्य 8-9 नगरपालिकाओं को बहाल किया है क्या हसनपुर की नगरपालिका को भी बहाल करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने एक प्रश्न भी दिया था लेकिन वह प्रश्न लगा नहीं। क्या मंत्री जी उदारता दिखाते हुए हसनपुर नगरपालिका को बहाल करने की कृपा करेंगे ?

श्री ए.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली सरकार ने हसनपुर म्यूनिसिपल कमिटी को खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने उसे खत्म किया है गुनाह तो उन्होंने किया है मैं यह जरूर चाहूंगा कि इनकी नगरपालिका को बहाल करने पर विचार किया जाये। स्पीकर सर, जैसा मैंने कहा है कि हमारी सरकार भाहर और देहात दोनों का ही सर्वांगीण विकास चाहती है। यदि किसी तरफ से ऐसा कोई

प्रस्ताव आता है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। मैं इसकी फाईल निकलवा कर देख लूंगा कि क्या मैरिट पर उस कमेटी को खत्म किया गया है और क्या ऐसे कोई कारण बने हैं जिनके कारण हम इसे रिवाइव कर सकते हैं तो हर हालत में उसको रिवाइज करेंगे।

Constitution of Administrative Reforms Commission

***837. Sh. Shamsheer Singh Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

a. Whether the Government of Haryana has constituted an Administrative Reforms Commission in the State;

b. if so, the terms and reference of the Commission;

c. whether any Administrative Reforms Commission was constituted previously; and

d. if so, what is the report of previous Commission ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)

क. हां, श्रीमान् जी।

ख. श्रीमान् जी, आयोग के संदर्भ की भाँति निम्नलिखित हैं :-

1. सरकार द्वारा सेवाओं की पूर्ण रूप से सुपुर्दगी में दक्षता, आर्थिक, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार में संगठनात्मक संरचना तथा विभागों के संचालन के ढंगों में उचित बदलाव की सिफारिश करना।

2. वातावरण सृजन करने के तरीकों की सिफारिश करना जहां सरकारी कृत्यकारी लोगों के प्रति सौजन्यता, समझदारी तथा पूर्ण सहायता के लिए उत्तरदायी हो।

3. सरकारी कृत्यकारियों के व्यवहार में अधिक पारदर्शिता एवं ईमानदारी को लाने के लिए भासन चलाने में सदाचार को उन्नत करने के तरीकों की सिफारिश करना।

4. मोनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली से सम्बन्धित विकेन्द्रीकरण कार्मिक तथा कार्यक्रम दोनों उपायों की सिफारिश करना।

5. प्रासकीय मामलों के तीव्र प्रस्तावों के प्रति अच्छे तालमेल के लिए भावितयों के अधिक विकेन्द्रीकरण हेतु उचित पहलुओं पर सिफारिश करना।

6. सभी विभागों में तथा स्तरों पर ई-गवर्नेंस को अधिक बढ़ावा देने के लिए सुझाव देना।

ग. नहीं, श्रीमान जी।

घ. श्रीमान जी, प्र न नहीं उठता।

श्री भामोर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाने के लिए मैंने 2005 के बजट सेशन में बोलते हुए कहा था और सरकार ने तीन साल के बाद इस आयोग का गठन किया है, देर आयद दुरुस्त आयद। स्पीकर सर, क्या उसकी रिपोर्ट पर अमल इसी सरकार के टैन्डोर में लागू हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह तो हाईपोथेटिकल सवाल है और यह रिपोर्ट आने के बाद की बात है। (विधन) पहले रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसको लागू भी करवाएगी। दलाल साहब, बहुत ही सीनियर और वाईड एक्सपीरियंस के व्यक्ति है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने यह बात यहां पर उठाई थी कि हरियाणा में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन की बहुत आवश्यकता है। कोई भी माननीय सदस्य जब कोई सुझाव देता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको गम्भीरता से लेते हैं और उस पर बाकायदा मन्त्रणा होती है। मन्त्रणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि इस कमीशन के गठन की जरूरत है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म

कमी इन की इन्टैरिम रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है फिर भी मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहूंगा कि कर्ण सिंह दलाल जी उनके पड़ोस में बैठते हैं और वे इस कमी इन के चेयरपर्सन भी हैं, वे बहुत सूझ-बूझ रखने वाले व्यक्ति हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमी इन की रिपोर्ट में बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव सरकार को देंगे।

**Recruitment to the post of Joint Director. Animal
Husbandry Department**

***914 Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state :-

(a) whether any direct recruitment to the post of Joint Director (Animal Husbandry) was made by the Government on the recommendation of HPSC during the year 2003;

(b) if so the name of the person and the date of requisition sent by the Administrative Department together with the date of advertisement and the date of recommendation letter of HPSC;

(c) whether there was any provision of direct recruitment of the post as specified in (a) above in the Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules 1995;

(d) whether the recruitment to post as mentioned in (a) above was contrary to the provisions of Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules 1995; and

(e) if so the action taken by the Government or proposed to be taken by the Government in this regard?

Agriculture Minister (Sardar B.S. Chatha) :

(a) Yes, Sir.

(b) Sir, Dr. Virender Singh was appointed as Joint Director (Animal Husbandry) on the recommendation of H.P.S.c. during 2003. The requisition was sent to H.P.s.C. on 5.6.2003 by the Government. The said post was advertised on 16.6.2003 and the recommendation was made by the H.P.S.c. on 22.8.2003.

(c) Yes Sir, as per amendment dated 9.5.2003 in Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules, 1995, there was provision for the direct recruitment.

(d) No Sir.

(e) Question does not arise.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी यह सप्लीमेंटरी है कि क्या मंत्री जी यह जानते हैं कि डॉ. विरेन्द्र सिंह पिछली सरकार के समय के मुख्यमंत्री जी के दामाद हैं और ये इस विभाग में डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए थे ? इनकी प्रमोशन ज्वॉयंट डायरेक्टर के पद पर नहीं हो सकती थी। इस विभाग ने 2003 में तमाम रूलज को बड़ी ही जल्दबाजी में बदला और इस पोस्ट को बाई प्रमोशन भरा जाना उचित समझा।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत विभाग में आन पड़ी थी कि एक व्यक्ति जो उन दिनों के मुख्यमंत्री के दामाद थे उनके लिए यह पोस्ट क्रिएट की गई और जल्दबाजी में रूलज अमेंड किए गए ? अध्यक्ष महोदय, जिस महोदय को इस पोस्ट पर अप्वायंट किया गया था आज वे श्रीमान कहां पर पोस्टिड है और क्या काम कर रहे हैं ?

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे नहीं पता है कि दामाद है कि नहीं है लेकिन मुझे यह सुनने में जरूर आया था कि यह आदमी पुराने चीफ मिनिस्टर के दामाद हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य की यह बात दुरुस्त है कि बड़ी हरीली यह ऐड की गई थी। 5 तारीख को अमेंडमेंट की गई थी और अलगी 5 तारीख को पब्लिक सर्विस कमिशन को लिखा गया था। 16.6.2003 को पब्लिक सर्विस कमिशन ने विज्ञापित किया था। 26 तारीख को अप्वायंट कर दिया और 27 तारीख को ज्वायनिंग भी करवा दी। लेकिन इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि यह सिलैब इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्विस कमिशन ने की है और वह ऐडवर्टाइजमेंट के थ्रू की है। हां, यह बात ठीक है कि यह अप्वायंटमेंट बहुत जल्दी में की गई है। जहां तक इनका सवाह है कि वह आजकल कहां पर है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि उसने स्टडी के लिए छुट्टी ली हुई है। पहले छुट्टी 188 दिन की थी, फिर 366 दिन की छुट्टी ली और फिर दोबारा से 187 दिन

की छुट्टी ली है। यह टोटल 711 दिन की छुट्टी बनती है जोकि अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या विभाग ने इस बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि यह व्यक्ति वाकई में पढ़ाई-लिखाई के लिए छुट्टी पर है या तो काम की खानों आदि की देखभाल कर रहा है ?

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, उसने डिपार्टमेंट को छुट्टी के लिए अप्लाई किया और डिपार्टमेंट ने उसको छुट्टी दी है। लेकिन विभाग 120 दिन से ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है। जब उसने ज्यादा छुट्टी के लिए अप्लाई किया था तो उसका केस फाईनांस डिपार्टमेंट को भेजा गया था और अब फाईनांस डिपार्टमेंट ने उसे छुट्टी देने के लिए अलाऊ कर दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि वह विदेश में 'कान' में कुछ स्टडी कर रहा है या खानों में कुछ कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, कर्ण सिंहजी यह जानना चाहते हैं कि Is there any documentary proof that he has really gone on study leave ?

सरदार एच.एस. चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, वह परमिशन लेकर स्टडी के लिए गया है। वह स्टडी कर रहा है या नहीं कर

रहा है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन हम इस बात की जांच करवा लेंगे।

15.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जब इनकी नियुक्ति कर दी गयी तो इसके बाद इनको अप्वायंटमेंट लैटर दिया गया। इस अप्वायंटमेंट लैटर की तीसरी भात में यह जिक्र है कि the particulars of these examination/test/training etc. which the candidate was required to go through during the period of probation. इसलिए इसकी तो इंफोर्मे इन डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि इनकी नियुक्ति की भातों के मुताबिक प्रोबे इन पीरियड में इनकी कौन-कौन सी परीक्षाएं ली गयी, कौन-कौन से इनके टैस्ट लिए गए और उन परीक्षाओं और टैस्ट्स की क्या-क्या स्थिति रहीं? मंत्री जी ने जो यह कहा कि वे नहीं जानते तो क्या मंत्री जी सदन की आ वास्त करेंगे कि इनकी जांच करवायी जाएगी कि जो ये छुट्टी लेकर पढ़ाई करने गए हैं और पढ़ाई ये नहीं कर रहे हैं तथा अगर यह सच्चाई है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

सरदार एच.एस. चट्ठा : स्पीकर सर, बहुत बढ़िया बात मेरे लर्नड भाई ने की है, हम पूरी जांच करवाएंगे। अगर वे पढ़ाई करने के लिए छुट्टी लेकर गए हैं और यदि वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो we will proceed against him.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपने दलाल साहब के दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या उनके टैस्ट लिए गए या नहीं और अगर लिए गए तो उनकी क्या स्थिति रही ?

सरदार एच.एस. चट्ठा : स्पीकर सर, जहां तक इनके दूसरे सवाल की बात है, अगर किसी आदमी के एक साल या दो साल के प्रोबे इन पीरियड में उसके खिलाफ कोई बात नहीं है और यदि वह ठीक काम कर रहा है तथा यदि आपके पास पोस्ट है तो हमें उसको रैगुलर तो करना पड़ेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्योंकि पिछली सरकार ने अपने लोगों को, अपने रि तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया है मंत्री जी ने कहा है कि उनके खिलाफ जांच करवाएंगे कि वह पढ़ाई कर रहा है या नहीं accordingly they will take the action. इसलिए अब आप बैठें।

Illegal Mining

***887 Sh. Bhupinder Chaudhary :** Will the mines and Geology Minister be pleased to state whether it is a fact that illegal mining in the villages like Gairatpur Bas, Manesar, Sikohpur, Naurangpur etc. is still going on despite the orders of the Hon'ble Supreme Court banning the activity of mining

in Gurgaon District, if so, the steps taken by the Government to check the illegal mining in Gurgaon District ?

Industries Minister (Shri Lachman Dass Arora) :

No, Sir.

श्री भूपेन्द्र चौधरी : स्पीकर सर, सुप्रीम ने ने भी यह कहा था कि गुड़गांव जिले में अवैध माईनिंग नहीं होगी। जब फारैस्ट कंट्रोलर वहां पर एक दिन गए तो वहां पर माईनिंग चल रही थी। स्पीकर सर, यह माईनिंग वहां पर लगातार चल रही है जबकि डिपार्टमेंट यह कहता रहा है कि वहां पर माईनिंग नहीं चल रही हैं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर रैगुलर माईनिंग हो रही है। जां वहां पर अवैध माईनिंग की जा रही है उनको संबंधित ऑफिसर ने नोटिस भी इ जु हुए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस अवैध माईनिंग को रूकवाएंगे ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, जहां तक मेरे आदरणीय साथी का प्र न है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई माईनिंग नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य तो कह रहे हैं कि वहां माईनिंग चल रही है। क्या आप वहां पर अपने विभाग की कोई टीम भेजकर इस बारे में जांच करवाएंगे ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर साहब, हमने इस बारे में सारा सर्वे करवाया है। छोटे मोटे 14 केसिज में ही इस बारे में

एफ.आई.आर. लौज हुई है और इनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है ।

Setting-up of SEZ by Reliance Industries Limited

*810 Dr. Sita Ram : Will the Industries Minister be pleased to state:(a) whether the Government is aware of the fact that the Reliance Industries Limited is likely to set-up a Special Economic Zone in the State;

a. whether the Government is aware of the fact that the Reliance Industries Limited is likely to set-up a Special Economic zone in the state;

b. if so, the name of place and the total acreage of land (Agricultural and Non-Agricultural) acquired by the Government for the setting up of above said SEZ and the date on which possession of the said land was given together with the details thereof; and

c. the rate at which compensation was being paid to the owners of the land and the rate at which the above said land was being given to the Reliance Industries Limited ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) (b) State Government acquired land for setting up of Special Economic Zone by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited. (HSIIDC) measuring 1484 Acre 4 Kanal19 Marla in the

revenue estate of villages Kbandsa, Narsinghpur, Mohammedpur Jharsa, Garoli Khurd and Harsaru in tehsil & district, Gurgaon, out of which land measuring 13 83 .68 acre was transferred to Reliance Haryana SEZ Limited, a joint venture company of HSIIDC and Reliance Venture Limited (100% owned subsidiary of Reliance Industries Limited) for the setting up of Special Economic Zone. The possession of the land was given on 6.12.2006. The details of the land are as under :

1.	Village Khandsa	- 129.52 acre
2.	Village Mohammedpur Jharsa	- 298.62 acre
3.	Village Narsinghpur	- 42.26 acre
4.	Village Garoli Khurd	- 242.59 acre
5.	Village Harsaru	- 1670.69 acre

- (c) The compensation was paid to the owners of the land at the average rate of RE. 21.17 lacs per acre. The land was transferred to Reliance Haryana Special Economic Zone Limited at the rate of Rs. 27.52 lacs per acre.

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब प्र नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Foreign tour by the Chief Minister

***888. Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) the tour undertaken by the Chief Minister to foreign Countries after taking over as Chief Minister in the State in March, 2005, together with the details, of countries visited.

(b) the total amount incurred on the said tours and the names of the Officers/MLA's accompanied, together with the detail of achievement made therefrom, and

(c) the details of agreement / MOU signed?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क एवं ख) मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दौरे, वहन किए गए खर्च, साथ गए अधिकारियों / विधायकों के नाम तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वर्ष	देशों के स्थानों के नाम	प्रतिनिधियों का विवरण	की गई यात्रा की तिथि	खर्च की गई धनराशि (रूपयों में)	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	2005-06	जापान तथा कोरिया, गण-राज्य	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री, एम.एल. तायल, आई.	26.11.05 से 4.12.05 तक	26,10,074	दौरों से 2200 करोड़ रुपये का निवेदन मिला। सैमसंग, याकूल्ड, वाइकेके, मितसुई

			<p>ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी.के. चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, अ गोक लवासा, आई. ए.एस., रेजीडेन्ट आयुक्त, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, डी.आर. धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम.</p>			<p>किंजौक, कम्पोनैन्टस, अ गही ग्लास, युकालफयूल सिस्टमज, इंडिया जापान लाइटिंग, केहिन फाई, एनटीएन मैन्युफैक्चरिंग, फाइन कैमिकल्ज, पोस्को स्टील, कायकोडीयर एब्रेसिब, डायमंड इलैक्ट्रिकल तथा पारकल</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>एस. चोपड़ा, वि शेष कार्यकारी अधिकारी-II/मुख्यमंत्री, सुरजीत सिंह, सीटीपी / हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, राके । टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।</p>		<p>इंजिनियरिंग जैसी जापानी एवं कोरियन कम्पनियों ने 837.19 करोड़ रुपये के निवे । के साथ हरियाणा में अपनी परियोजनाएं क्रियान्वित कर दी है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने 4895 करोड़ रुपये का पूंजी निवे । करके हाल ही में आईएमटी मानेसर में वाणिज्यिक</p>
--	--	--	---	--	--

						उत्पादन भुरू कर दिया है। इस कम्पनी का 10,000 करोड़ रूपये निवे । करने की योजना है, जिसमें इसके वैण्डज द्वारा 5000 करोड़ रूपये भामिल है।
2.	2006-07	नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यू.के. तथा स्पेन	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री हरियाणा, कै. अजय	8.10.06 से 19.10.06 तक	82,14,598	दौरों से 10 वर्षों के दौरान 12000 करोड़ रूपये का विनिवे । मिलेगा। अभिरूचि का एक

			<p>सिंह यादव, राजस्व मंत्री, एम.एल. तायल, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी.के. चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, अ गोक लवासा, आई.ए.एस., रेजीडेन्ट आयुक्त, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, डी.आर.</p>		<p>वक्तव्य हस्ताक्षरित हुआ, जो हरियाणा में एक यूरोपियन टैक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए डच हरियाणा बिजनैस कन्सोर्टियम के साथ हस्ताक्षर किए गए। ओसराम (सिमन्ज एजी की एक सहायक कम्पनी) जे.सी.बी. तथा अलस्टोम ने भी राज्य में परियोजनाओं को</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम. एस. चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/मुख्यमंत्री, भाादी लाल कपूर, वरिष्ठ सचिव / मुख्यमंत्री, राके टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, मनोज पाल सिंह, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा</p>		<p>स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई फोलोअप के रूप में कुण्डली में मैसर्ज ओसराम को 10 एकड़ प्लॉट अलॉट किया गया है तथा मैसर्ज जे.सी.बी. को भी उनके विस्तार परियोजना के लिए 10 एकड़ प्लॉट सैक्टर, 58 फरीदाबाद में, गांव मांगर में 500 एकड़ पर एक यूरोपियन</p>
--	--	--	--	--	---

			राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।			टैक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें उच्च हरियाणा बिजनैस कन्सोर्टियम तथा हरियाणा औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से एस.पी.वी. के तहत शामिल होना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम को इस
--	--	--	-----------------------------------	--	--	---

						परियोजना में भोयर होल्डिंग की 10 प्रतिशत के बराबर स्वीट इक्विटी मिलेगी।
3.	2006-07	चीन तथा सींगापुर	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, फूल चंद मुलाना, शिक्षा मंत्री, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री हरियाणा, धर्मवीर सिंह, मुख्य संसदीय सचिव, भाादी लाल बत्रा, विधायक,	26.11.06 से 4.12.06 तक	26,04,431	यह दौरा इन्टरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चीन तथा बाहरी मामलें मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य आदान-प्रदान कार्यक्रम का एक

			<p>अध्यक्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एम.एल. तायल, आई. ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी.के. चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, डी.आर. धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम.</p>		<p>हिस्सा था। अभिरूचि के क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन (सेज) तथा चीन में संरचना विकास का अध्ययन करना था।</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>एस. चोपड़ा, वि शेष कार्यकारी अधिकारी-II/मुख्यमंत्री, भादी लाल कपूर, वरिष्ठ सचिव / मुख्यमंत्री, राके ा टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, मनोज पाल सिंह, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास</p>		
--	--	--	---	--	--

			निगम।			
4.	2007-08	यू.एस.ए., कनाडा एवं जर्मनी	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, फूल चंद मुलाना, अध्यक्ष बीस सूत्री कार्यक्रम, कैप्टन अजय सिंह यादव, सिंचाई मंत्री, भाादी लाल बत्रा, विधायक, अध्यक्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एम.एल. तायल, आई. ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी.के.	8.10. 2007 से 20. 10.07 तक	1,04,73,555	इन दौरों से 3750 करोड़ रुपये का निवेा प्राप्त हुआ। खाद्य संरक्षण तथा प्रोसैसिंग उद्योग में स्पैक्ट्रम इन्टरनेशनल एल. एल.सी./मैसर्ज होलीस्टर इन्क (यू. एस.ए.) जो चिकिस्सा देखभाल (ओस्टोमी) उत्पादों का एक विख्यात

			<p>चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, डी.आर. धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम. एस. चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/मुख्यमंत्री, भाादी लाल कपूर, वरिष्ठ</p>		<p>निर्माता है, का 100% का इओयू स्थापित करने का प्रस्ताव है। रिको ऑटो इन्डस्ट्रिज लिमिटेड तथा मैग्मा पावर ट्रेन के मध्य ऑटो मोबाइल में समान संयुक्त उद्यम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डॉ. फ्रेजा जो औरल हाइजीन में एक विख्यात ब्राण्ड</p>
--	--	--	---	--	--

		<p>सचिव / मुख्यमंत्री, सलील नारंग, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, राके । टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम ।</p>		<p>के अध्यक्ष है । उन्होंने गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस सेज की स्थापना के लिए घोशणा की मोन्टगोमरी कॉलेज तथा हरियाणा राज्य के एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए थे । जिसके अनुसार मोन्टगोमेरी कॉलेज, हरियाणा के वि व विद्यालय के साथ व्यवसाय पाठ्यक्रम भागीदारी</p>
--	--	--	--	--

						<p>नीति योजना, विद्यार्थी अदला- बदली तथा विचार-विमर्श के प्रावधान के माध्यम से राज्य को कॉलेज के उत्तम व्यवसायों को अपनाने में सहायता करेगा। हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए दो प्रस्ताव भी</p>
--	--	--	--	--	--	---

						प्राप्त हुए।
					2,39,02,658	

नोट : यू.एस.ए. कनाडा एवं जर्मनी से संबंधित विदे गी दौरे जो 8 से 20 अक्टूबर, 2007 तक किए गए हैं, उनका खर्च अस्थाई है तथा खर्च/लेखा एवं ऑडिट को अन्तिम रूप देने की भांति पर है।

हस्ताक्षर किए गए समझौते / एम.ओ.यू. का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. अभिरूचि का एक विवरण (एस.ओ.आई.) 12000 करोड़ रुपये (10 वर्षों की अवधि में 2 बिलियन यूरो) के निवे ग से हरियाणा में एक यूरोपियन टैक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम तथा डच हरियाणा बिजनैस कन्सोर्टियम के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था।
2. मोन्टगोमरी कॉलेज तथा हरियाणा राज्य के मध्य एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार मोन्टगोमरी कॉलेज का हरियाणा

के वि विद्यालयों के साथ व्यवसाय, विकास, पाठ्यक्रम भागीदारी नीति
योजना विद्यार्थी अदला-बदली में सहायता करेगा।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Qualification of Members of H.P.S.C.

***113. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the qualifications and categories of Official/Non-official Members and Chairmen of Haryana Public Service Commission since 1996 till date alongwith the dates of their appointment and retirement/resignation.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी, सूचि सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों की दिनांक 1.1.1996 से अब तक की सूचि।

क्र.स.	अध्यक्षों / सदस्यों के नाम	योग्यताएं	श्रेणी सरकारी / गैर-सरकारी	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति / त्यागपत्र की तिथि
1.	श्री गोविन्द टुकराल, सदस्य	एम.ए. (अंग्रेजी)	गैर-सरकारी	26.5. 1996	14.3. 2002 त्यागपत्र 3.7.1997

2.	श्री एन. एन. यादव, सदस्य	एम.एस.सी. (भौतिकी)	सरकारी	18.9. 1996	3.5.2002
3.	श्री एम. एस. राठी, सदस्य	बी.ए.	सरकारी	26.5. 1996	14.5. 1998
4.	श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य	बी.ए., एल. एल.बी.	गैर-सरकारी	17.6. 1998	16.6. 2004
5.	श्री दयाल सिंह, सदस्य	बी.एस.सी. (इंजिनियरिंग)	सरकारी	3.7. 1998	2.7.2004
6.	श्री जगदीश राय, सदस्य	एम.ए. बी.ए. (ऑनर्स)	सरकारी	18.7. 1998	17.7. 2004
7.	श्री एल. डी.	बी.ए. एल. एल.बी.	गैर-सरकारी	22.9. 1999	31.7. 2000

	मैहता, अध्यक्ष				
8.	श्री एम. एस. भास्त्री, सदस्य	बी.ए. एल. एल.बी. भास्त्री (ओ. टी.)	सरकारी	28.2. 2000	27.2. 2006 त्यागपत्र 6.12. 2004
9.	श्री एम. एस. सैनी, सदस्य	बी.ए.एम.एस	गैर-सरकारी	7.7. 2000	6.7.2006 त्यागपत्र 1.12. 2004
10.	श्री के.सी बांगड, अध्यक्ष	पी.एच.डी. (यू.के.) आर. आई.टी.ई. और ए.वी. एच.फैलो	गैर-सरकारी	2.8. 2000	1.8.2006 त्यागपत्र 1.12. 2004
11.	श्री गुलान भारद्वाज,	बी.ए. एल. एल.बी.	गैर-सरकारी	4.4. 2001	9.8.2004

	सदस्य				
12.	श्री एस. के.गुप्ता, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	4.4. 2001	3.4.2007 त्यागपत्र 5.7.2004
13.	श्री प्रदीप चौधरी, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	10.5. 2002	9.5.2008 त्यागपत्र 5.7.2004
14.	श्री डूंगर राम, सदस्य	एम.ए. (अंग्रेजी)	सरकारी	5.7. 2004	9.6.2009
15.	श्री छतर सिंह, सदस्य	बी.ई.(बिजली)	सरकारी	5.7. 2004	4.7.2010
16.	श्री युद्धवीर सिंह, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	5.7. 2004	4.7.2010
17.	श्री	बी.ए.	गैर-सरकारी	5.7.	4.4.2010

	सतबीर सिंह, सदस्य	(ऑनर्स) एल. एल.बी.		2004	
18.	श्री ओम प्रकाश, सदस्य	बी.ए. एल. एल.बी.	सरकारी	10.8. 2004	9.8.2010
19.	डॉ. रनबीर सिंह हुड्डा, सदस्य	एम.एस.सी. (एग्रोनोमी), पी.एच.डी., एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	10.8. 2004	9.8.2010
20.	श्री मेहर सिंह सैनी, अध्यक्ष	बी.ए. एम.एस	गैर-सरकारी	1.12. 2004	30.11. 2010
21.	श्रीमती संतोश सिंह, सदस्य	एम.एस.सी., बी.एड.	गैर-सरकारी	1.12. 2004	30.11. 2010
22.	श्री राम	एम.ए.	सरकारी	15.12.	14.12.

	कुमार क यप, सदस्य	(अर्थ गास्त्र), एल.एल.बी.		2004	2010
--	-------------------------	------------------------------	--	------	------

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :
Sir, I beg to lay on the Table-

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2005-06, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 7th Annual Report of Dakshin Haryana Bijji Vitran Nigam Limited for the year 2005-2006, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 8th Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर
मतदान (पुनरारम्भ)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अभिभाषण पर बात करने से पहले अपने साथियों की ही तर्ज पर मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अच्छा भवन और अच्छी सराउंडिंग्स हमें दी है। इसके लिए आपको और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से लेकर सभी को बहुत बधाई दंता हूं। स्पीकर सर, जिस प्रकार से वार्षिक योजना का आकार विगत तीन वर्षों में लगभग तीन गुणा बढ़ा है इसके लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार बधाई के पात्र है। हर तरफ काफी तरक्की के काम हो रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। सबसे ज्यादा लैंडमार्क काम सरकार ने किसानों की जमीनों के रेट देकर किया है। मेरे हल्के में पिछले राज में 1.5 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से जमीन अधिग्रहण के मामले में किसान को उसकी जमीन का मुआवजा दिया जाता था। आज यह स्थिति है कि जब किसी प्रोजैक्ट के लिए या विकास के कार्य के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो किसान निरा । नहीं होता है। वह बहुत बड़ा लैंडमार्क निर्णल सरकार ने लिया है जिसके तहत किसान को 33 साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष और 30 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न स्कीमों में दिये जाते हैं और उसमें क्रम 1: 500 रुपये और एक हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से बढ़ौत्तरी भी की जाती है। हमने भी इतने वर्षों तक किसान की राजनीति की है लेकिन ऐसी

योजना पहले कभी नहीं देखी। इसी वजह से दिल्ली के केन्द्र के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर जिक्र किया। सारे देश में हरियाणा की तरज पर इस फैसले को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। ऐग्रीकल्चर पर आते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नेचुरल कैलेमिटी पर भी सरकार ने किसान की बहुत ज्यादा मदद की है। इस लाइन पर मेरा यह सुझाव है कि जब ओलावृष्टि होती है या कोई अन्य नुकसान होता है तो उस वक्त किसान की सारी आसानी उसकी फसल पर लगी हुई होती है। आमतौर पर किसान को गेहूं और जीरी में 20-25 हजार रुपये का पैकेज मिलता है। मेरा निवेदन है कि सरकार के पास क्योंकि इस समय रिसोर्सिज बहुत ही अच्छे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए। आज के संदर्भ में कुछ कीमतें बढ़ा दी हैं और कुछ कीमतें किसानों की जिंसों की भी बढ़ी हैं लेकिन फिर भी पर-एकड़ मुआवजे का रेट 50 परसेंट जरूर बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। इं योरेंस की सरकार ने बढ़िया नीति लागू की है लेकिन मेरा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि इं योरेंस का जो लाभ किसान को होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। एफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है। इं योरेंस कंपनीज किसान को बहुत ज्यादा ऐक्सप्लॉयट करती है। सरकार से भी प्रीमियम की राशि ले लेती है और व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं मौका लगता है तो प्रीमियम राशि लेने से नहीं चूकती है लेकिन जब देने का समय आता है तो तरह-तरह की अड़चनें अड़ाने की चेश्ठा की जाती है। सरकार

को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी ओलावृष्टि होती है तो पूरे गांव के किसान को उसका नुकसान नहीं होता है। जब कभी फलड आता है तब भी पूरे गांव को नुकसान नहीं होता है। यदि किसान का किसी किनारे पर नुकसान हो जाता है तो वह इस इं योरेंस के लाभ से वंचित रहेगा। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने गन्नौर में नयी मंडी बनाने का पे ाक ा की है। काफी अर्सा पहले यह मंडी कुंडली में बनाने की बात कही गई थी। पिछली सरकार ने वेस्टेड इंट्रस्ट की वजह से जमीन और जगह इस्तेमाल की और इंडस्ट्रीज के लिए प्लाट्स देकर मकसद हासिल किया। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने कोआप्रेटिव लोन के ऊपर लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का प्रावधान किया है। इससे जनता जनार्दन के सामने और लेनिज के बैनीफिसरीज के सामने यह सवाल रखा कि आप अपना असल पैसा अदा कर दीजिए आपका जितना भी ब्याज है वह माफ हो जायेगा। बीच-बीच में भी कर्जा काफी के नाम का इस बारे में कभी ब्यान आ गया कभी किसी ब्यान आ गया और लोग इस लोन का सिर्फ 400-450 करोड़ रुपये के लगभग फायदा उठा पाये जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी श्री बिरेन्द्र सिंह जी ने कहा। लेकिन एक बड़ी विडम्बना दिल्ली की केन्द्र सरकार ने की कि उसने 60 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ करने की घोशणा की। दे ा भर के अन्दर इस बात की बहुत चर्चा है और

किसान बहुत खुश है। लेकिन एक और चर्चा किसानों की रूप रेखा की अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व बनता है खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने किसानों को साधन-सम्पन्न बनाने का एक बीड़ा उठाया है। हालांकि पार्लियामेंट में अभी इस बारे में डिसकशन होना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस लोन माफी के जो पैसे का वितरण है एम.पी.जे. के माध्यम से इस तरह से करवाये यह क्लीयर करवाया जाए कि जो विलफुल डिफाल्टर्स हैं और दूसरे वाकई गरीबी के कारण डिफाल्टर्स हैं। जो बिलकुल डिफाल्टर्स हैं उन लोगों के किसी न किसी तरह से सरकार को पर कतरने चाहिए वरना वे आगे भी इसी तरह से डिफाल्टर्स होते रहेंगे। जैसा हमने अपना कर्जा अदा कर दिया लेकिन हम बीच में फंस गये। न तो हमें इसका फायदा मिला न हम डिफाल्टर्स हैं। इस प्रकार की सिच्यूएशन को भी कवर करना चाहिए कि 60 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के अन्दर यह होना चाहिए कि जो वाकई लोन लेकर देना चाहते हैं उनको भी इसके अन्दर पूरा लाभ मिलना चाहिए ताकि उससे हमारा लेन-देन का सिस्टम है और जो हमारा लेन-देन का बैंकिंग सिस्टम है उसका एतगार बना रहना चाहिए। क्योंकि हम भी कोओपरेटिव सैक्टर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो 60 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया है उसको किसी न किसी प्रकार से जो वाकई में अपना लेना-देना जानते हैं उनको इस से लाभ हो सके। वरना बैंक फेल हो जायेंगे। आज ऐसा माहौल बन

जायेगा कि आई बार इस तरह के डिफाल्टर्ज ही फायदा उठायेंगे। यह गलत प्रथा तो हमारे साथ बैठे विपक्ष के साथियों ने भुरू की थी। अगर इस तरह से डिफाल्टर्ज को ही फायदा होता रहा तो आगे से कोई भी लोन वापिस नहीं करेगा। स्पीकर सर, मैं बहुत अर्से से कोआप्रेटिव सैक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, कोआप्रेटिव सोसायटी के अन्दर 50 सालों की जद्दोजहद के बाद हम गांवों के खाद, पानी, कर्जा सारी चीजें पहुंचा पायें हैं। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट ने हर गांव के अन्दर सोसायटी का दफ्तर बना दिया था। मुझे कम से कम इस बात का खेद है कि उसमें 7-8 गांवों की सोसायटी को मिलाकर जो पैक बनाई है तो एक जगह जहां बैंक ट्रावल करते थे वहां हम ट्रावल करेंगे जिसके कारण इस पर बहुत सारा फण्ड वेस्ट होगा क्योंकि किसान अपनी हर जरूरत के लिए एक गांव से दूसरे गांव जायेगा और भायद जो हम इकोनोमिक की सुविधा देना चाहते हैं उसकी बजाए गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इस प्रकार की बात पी.ए.सी. की मीटिंग में भी आई थी और इस सवाल पर कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी माना था कि इससे काफी दिक्कत की ि कायतें सामने आई है और जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उन्हें इस बारे में स्टडी करवानी चाहिए ताकि जो फायदा आप करने जा रहे हैं ऐसा न हो कि किसान के फायदे की बजाए नुकसान ज्यादा हो जाये। स्पीकर सर, हमारे यहां खेती के तरीके बदल रहे हैं जो खेती के इम्प्लीमेंटस के ऊपर भारत सरकार ने सब्सिडी दी है।

मुझे बहुत खुशी है कि रोटोवेटर नया इम्प्लीमेंट आया है जिसके ऊपर पंजाब में इम्प्लीमेंट मनुफैक्चरर ने एक ड्रील लगा दी है जिसके बाद यह इम्प्लीमेंट एक ही ऑपरेशन में गेहूं की बिजाई कर देता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार इन इम्प्लीमेंट्स पर डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को दें। ऐसा न हो कि सरकार मनुफैक्चरर को सब्सिडी दे तो वे किसान को एक्सप्लॉयट करें। इस तरह से डीजल बचेगा और इससे साधन बचेंगे और पर्यावरण भी ठीक होगा। इसलिए इस रोटोवेटर इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप कन्कलूड कीजिए आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो बेतकमीती सुझाव है और जब आप कहेंगे तभी बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वैटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मुरा ब्रीड के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई जिले सिलैक्ट किए गए हैं उनमें मेरा जिला कैथल भी है। मुरा भैंसों की बहुत भारी कीमत हो गई है, एक-एक भैंस 30-30 हजार रुपये से लेकर एक-एक लाख रुपये तक की बिकती है और जैसा कि अभी एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि हर गांव के अंदर वैटरनरी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो मेरा सुझाव है कि हर गांव में वैटरनरी के रिप्रेजेंटेटिव की बजाए एक वैटरनरी डिस्पेंसरी बनाई जाए ताकि गरीब आदमी

जिनके जानवरी एमरजेंसी में मर जाते हैं उनके जानवर बच सकें और उनका नुकसान न हो। जिन लोगों का पशु पालन का काम है और वे दूध की पैदावार करते हैं तो मेरा सुझाव है कि दूध का कोई न कोई मिनीमम स्पोर्ट प्राइज होना चाहिए क्योंकि मिल्क प्रड्यूसर्स का बहुत एक्सप्लॉएटेड बन हो रहा है। मिल्क प्लांट को आदेना होना चाहिए कि हर गांव में मिल्क कोलैक्टिंग सेंटर होगा। दूधिए गांव से 8 रूपये किलो, कभी 10 रूपये किला और कभी 11 रूपये किलो के हिसाब से दूध लेते हैं लेकिन जब कभी दूध ज्यादा हो जाता है तो दूधिए रेट कम कर देते हैं और वे गरीब किसानों का पैसा लौटाते नहीं हैं। पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री ने वेवर्स की लाइन लगा दी है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने हर गरीब व्यक्ति को, हर क्लास को और हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं फोरैस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। फोरैस्ट में मेरा कुछ अनुभव भी है, पिछली सरकार में 'हरियाली' नाम की एक योजना थी, बड़े खेद की बात है कि उस योजना का एक-एक रूपया उस समय के स्थानीय एम.एल.एज. ने अधिकारियों के साथ मिलकर खाया है और एक भी पेड़ नहीं लगाया। यह ऐसा विभाग है जिसमें पेड़ लगाने में खर्चा आता है और उसको मेन्टेन करने में खर्चा कम आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां कहीं पेड़ लगे हैं वहां देखा जाए कि वे

बड़े हो रहे हैं या नहीं और उनकी पूरी तरह देखभाल होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इरीगे न में बहुत तरक्की हो रही है इसके लिए मैं इरीगे न मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ। इरीगे न के मामले में मेरे क्षेत्र में भी बहुत से काम हुए हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि जो नालों की अब रिपेयर ही रही है मैंने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था कि इसमें 9 इंच की दीवारें बननी चाहिए, 4 इंच की दीवार बनाने से वह ज्यादा देर चलती नहीं है और इससे नैनल रेवेन्यू वेस्ट हो रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि इन खालों की दीवारें 9 इंच की बनानी चाहिए इससे स्टेट का फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आब वाइंड—अप करें।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ में भी बहुत पैसा लगा है लेकिन इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की मोनीटरिंग की बहुत जरूरत है। इंदिरा गांधी पेयजल योजना के नाम से जो योजना चालू की गई है इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक—एक घर में कई—कई रा न कार्ड है और वे 5—5 टंकियां ले लेते हैं, एक टंकी लगा लेते हैं और 4 टंकियां बेच देते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में निरीक्षण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि बिजली की कमी है और बिजली की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। मेरे हल्के में 3 सब स्टेसन बन रहे हैं और 2 सब स्टेसन अपग्रेड हुए हैं और 3 और सब स्टेसन बनने की सम्भावना है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है, मेरे हल्के में भी जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो कई सड़कों की मंजूरी देकर आए थे, मुझे खुशी है कि उन सबके ऊपर टैण्डर्ज हो गए हैं आज उन पर काम होगा। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर सारे हरियाणा के रोड्स का इन्फ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में गेहूँ और जीरी का उत्पादन ज्यादा है लेकिन हमारे यहां जमीन की सोयल इतनी चिकनी है कि जीरी निकालने में दिक्कत होती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी कृषि की उत्पादन क्षमता ज्यादा है और जितने भी कंसोलिडेटेड पाथस हैं जहां-जहां से मार्किटिंग कमेटी को कृषि से आमदन ज्यादा है उन इलाकों में कंडीशन ऐसी है कि बरसात के मौसम में पानी रास्तों में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां सड़के पक्के तरीके से बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा वैसे मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप मुझे वाइंड-अप करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए शिक्षा के मामले में मैं कुछ कहना

चाहूंगा और मुझे बहुत खेद है कि सर्व शिक्षा अभियान के तरत दादरी के पास हम पी.ए.सी. के साथ डाइट की बिल्डिंग देखने के लिए गए। वहां सारे कमरे भरे हुए थे। हमने वहां पूछा कि कमरे भरे हुए क्यों है तो उन्होंने जवाब दिया हमें पता नहीं, सामान आया था और हमने रख लिया। हमने इस बारे में सारी रिपोर्ट भेज दी है। हमने कैथल में भी विजिट किया था वहां 31 मार्च को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 30 मार्च को पैसा आया और 31 मार्च तक सारा पैसा खूद-बूद हो गया।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, प्लीज अब आप बैठें। आप अपनी बात लिखवा कर भिजवा देना।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर वाइंड-अप करता हूँ। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो पी.एच.सी. दूर दराज के एरियाज में है वहां पर डॉक्टर नहीं जाते हैं। सरकार की तरफ से पी.एच.सी. के लिए करोड़ों रुपये लगाकर बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है लेकिन डॉक्टर के अभाव में लोगों को हेल्थ सुविधा नहीं मिल पाती। मेरे हल्के में भी तीन पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाई जायेगी इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनको सैलरी का अच्छा पैकेज दिया जाये ताकि वे सरकारी नौकरी करें। चाहे पी.जी.आई. के डॉक्टर हों या दूसरे डॉक्टर हों। आज के दिन डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको प्राइवेट

में ज्यादा सैलरी मिलती है। इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दें। इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक रूरल हैल्थ की बात है जब भी सरकार की तरफ से डॉक्टर की नियुक्ति की जाये तो जिस समय एडवर्टाइजमेंट की जाये उस समय पी.एच.सीज. की लिस्ट बना दी जाये कि जो-जो डॉक्टर सिलैक्ट होंगे उनको फलां-फलां दस पी.एच.सीज. में से किसी एक में काम करना पड़ेगा तभी जाकर हम रूरल हैल्थ की तरफ ध्यान दे पायेंगे वरना पी.एच.सीज. में कोई भी डॉक्टर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिविल वैलफेयर के बारे में भी कुछ बातें कहनी थी लेकिन समय कम होने की वजह से मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और आपसे मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपकी पार्टी के मेंबरज में से 43 मिनट एक मेंबर बोल चुके हैं, उसके बाद 77 मिनट एक और मेंबर बोल चुके हैं और उसके अलावा आपकी पार्टी के दो मेंबरज रामफल चिड़ाना जी और ई वर सिंह पलाका जी को भी 33 मिनट समय दिया गया। प्लीज आप बैठें, राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण पर अब तक 36 मँबर बोल चुके है। आप बजट पर बोल लेना। (विधन)

श्री उदयभान (हसनपुर, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया है मैं उसके अनुमोदन में और समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार का और केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि केन्द्र सरकार ने 60 हजार करोड़ रूपये के किसानों के कर्जे माफ करके बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया है। केन्द्र सरकार ने न सिर्फ किसानों के कर्जे माफ किए हैं बल्कि एक टाईम बाउंड समय भी निर्धारित किया है कि 30 जून तक सभी के कर्जे माफ कर दिये जायेंगे और भविष्य में कर्ज पर ब्याज की दर भी 7 प्रति शत की गई है उसकी जितनी सराहना की जाये वह कम है। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी पदासीन हुए।) सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह के क्रांतिकारी कदमों की भुरुआत उन्होंने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश से भुरु की जिसका अनुसरण हमारी केन्द्र सरकार ने भी किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सत्ता सम्भालते ही किसानों के 1600 करोड़ रूपये के बिजली के बिल माफ किए। उसके बाद सहकारी बैंकों के, लैंड मोरटगेट के, हरियाणा कल्याण निग के, बैकवर्ड कल्याण निगम के लाई माई का सारा ब्याज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफ करके बहुत ही

सराहनीय कदम उठाया था और हमारी सरकार के यही कदम केन्द्र सरकार के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता के हाउस टैक्स, चुल्हा टैक्स माफ किए और गेहूं तथा धान के भाव भी बढ़वाये। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में जो माहौल बना उससे केन्द्र सरकार ने प्रेरणा लेकर किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में किसानों से भी दलित, पीड़ित, अपेक्षित वर्ग है जो भैंस, रेहड़ा, जूती, परचूनी आदि रोजगार के लिए लोन लेते हैं, उनका भी कर्जा माफ होना चाहिए। यदि केन्द्र स्तर पर इस तरह की पहल नहीं होती है तो हरियाणा सरकार को अपने स्तर पर इन वर्गों के कर्जे माफ करने चाहिए। ऐसा करने पर बहुत उदार संदेश पूरे प्रदेश में और देश में जायेगा। इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा जिन लैंड लैस लोगों को, दलित उन कर्जों पर दस हजार रुपये की लिमिट रखी हुई है। सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन 25-30 हजार रुपये से कम में भैंस भी नहीं खरीदी जा सकती। जो यह दस हजार रुपये की लिमिट बनी हुई है यह बहुत पुरानी बनी हुई है इसलिए इसको दस हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये किया जाये ताकि गरीब हरिजन भाई कर्जा लेकर अपना काम धन्धा भुरु कर सकें। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो गरीब तबका है जो

रोज कमाता है और रोज खाता है और जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती तो उसे भूखा भी सोना पड़ सकता है। जिसको गेहूं, चावल, तेल, दाल और सब्जी भी सभी चीजें मोल खरीदनी पड़ती है। महंगाई की चक्की में सबसे ज्यादा यही वर्ग पिस रहा है। इस वर्ग को आपन ढाई तीन साल पहले मिनीमम वेजिज 3510 रूपये करके बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी। लेकिन अब ढाई तीन साल में जो महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मिनीमम वेजिज को कम से कम 5 हजार रूपये मासिक किया जाये। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार ने रेवेन्यु रिसीट्स के बारे में कहा है कि 2004-2005 में जो रेवेन्यु रिसीट्स 11,149 करोड़ रूपये थी वे तीन साल के बाद 2007-2008 में बढ़कर 19,630 करोड़ रूपये हो गई हैं जो कि 75 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। यह इस बात को भी दिखाता है कि हमारी सरकार का वित्त प्रबन्धन कितना बेहतरीन है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से प्लान बजट में भी तीन गुणा बढ़ौत्तरी की गई है और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 21.55 प्रतिशत का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार द्वारा ओलावृष्टि के नुकसान की भरपाई के लिए मौके पर जाकर एक-डेढ़ महीने के अन्दर जो तीन हजार, चार हजार और पांच हजार का मुआवजा दकर जो 208 करोड़ रूपये की राहत किसानों को प्रदान की गई उसके लिए भी यह सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। जबकि

पहली वाली सरकार द्वारा महज 200 रूपये, 300 रूपये, 400 रूपये मुआवजे के रूप में दिये जाते थे। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो 11 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने पार्टी अध्यक्ष को और मंत्रिमण्डल सहयोगियों को अपनी कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र का एक पैरा थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि श्री चौटाला के निरंकुश भासन में कमजोर वर्ग खास कर महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही थी। कमजोर तबका अपने आपको सुरक्षित महसूस करे इसके लिए प्रत्येक प्रयास किया जायेगा। अन्य कमजोर तबकों को भी जमीन दी जायेगी। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और कमजोर तबकों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराये जायेगे। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों के लम्बित कोटे को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर निपटाया जायेगा। आरक्षण नीति को पूरी भावना के साथ लागू किया जायेगा। चेयरमैन साहब, इस सम्बन्ध में कई मामलों में सरकार द्वारा अभूतपूर्व नियर्ण लिये गए हैं। जैसे लैंडलैस लोगों को आवासीय प्लॉट देने का निर्णय लिया गया है यह हमारी सरकार की एक बहुत ही भावदार उपलब्धि है। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भौड्यूल्ड कास्ट के छात्र-छात्राओं को पहली क्लास से लेकर हायर क्लासिज तक वजीफा देने का क्रांतिकारी कदम उठाकर एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। माननीय

मुख्यमंत्री महोदय के इस बेहतरीन कार्य को आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पायेगी। इसके लिए भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिल से बार-बार सराहना करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से 'इंदिरा गांधी पेयजल योजना' के तहत 8 लाख दलित परिवारों को मुफ्त पानी का कनैव 1न और 200 लीटर की पानी टंकी दी गई है यह भी सरकार की एक भानदार उपलब्धि है। इसके साथ ही हमारी पुलिस कांस्टेबल के बी-1 के टैस्ट में रिजर्वे 1न की मांग थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मान लिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी जिसे हम प्रत्येक सै 1न में उठाते रहे थे और वह मांग थी 85वें संविधान सं 1ोधन को लागू करने की। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय नं 6 दिसम्बर, 2006 को घोशणा की कि 85वां संविधान सं 1ोधन हरियाणा में लागू कर दिया जायेगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मंत्री परिशद् में भी रखा और उसे पूरी भावना के साथ लागू करने का एलान किया। लेकिन कुछ तो अधिकारियों के कारण और कुछ अन्य कारणों से उसमें एक लाईन जोड़ दी गई कि वह 16 मार्च, 2006 से लागू होगा। जबकि वह 17 जून, 1995 से लागू होना चाहिए था और इस प्रकार 11 साल की सीनियोरिटी एक लाईन में खत्म कर दी। इसकी वजह से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस 85वें संविधान सं 1ोधन को पूरी भावना के साथ जिस भावना

से इसको लागू करने की घोशणा की गई थी उसी के अनुरूप इसको 17 जून, 1995 से लागू किया जाये ताकि उसका समुचित लाभ सम्बन्धित लाभार्थियों को मिल सके। इसमें सबसे बड़ी बात बैकलॉग की है। जो हमारी रिजर्वे इन पॉलिसी है उसके बारे में आपने बार-बार तीन साल पहले भुरु से ही राज्यपाल के पहले अभिभाषण में भी, बजट से इन में भी और चुनाव घोशणा पत्र में भी यह वायदा किया था कि हम बैकलॉग को पूरा करेंगे लेकिन हर विभाग में भौड्यूल्ड कास्ट का और बैकवर्ड क्लासिज का बैकलॉग पड़ा हुआ है। हर विभाग में बैगलॉग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब जो गेस्ट टीचर बैकलॉग बेसिज पर लगाये गये हैं उनमें से भौड्यूल्ड कास्ट के साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है और उनको पूरा कोटा नहीं मिला। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकारी, अर्ध-सरकारी और बोर्ड/कारपोरे तानों में भौड्यूल्ड कास्ट के 30 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। इस बैकलॉग को पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, आप वाइंड-अप करें।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई स्पे ाल ड्राईव चला कर एक निश्चित समयावधि में पूरा करने का कश्ट करें। जिस तरह से आपने एस.सी.ज./बी.सी.ज. के लिए क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए इस

बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए जायें। रोस्टर प्रणाली को भी सख्ती से लागू किया जाये। इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य प्राइवेट संस्थाओं में जिसमें एम. बी.ए. व एम.सी.ए. वगैरह की पढ़ाई की जाती है, वहां पर रिजर्वे इन पॉलिसी को कंसीडर नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन संस्थाओं में भी दाखिले के समय रिजर्वे इन पॉलिसी को लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए दो-तीन बातें ही और बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब होडल में गये थे तो उन्होंने बहुत सी घोशणाएं की थी। उनमें से बहुत सी घोशणाएं पूरी हो गई जबकि कुछ बाकी है। जैसे मिनी सैक्रेटेरिएट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, होडल में सीवरेज का काम चल रहा है, पानी का काम चल रहा है, आई.टी.आई. का तथा सड़कों का काम भी चल रहा है। लेकिन कुछ घोशणाएं अब भी बाकी है। पी.एच.सी. सिहोर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 18 दिसम्बर, 2005 को यह घोशणा की गई थी। 2 साल हो गये लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। हसनपुर में यमुना पुल का काम है, पुलिस स्टे इन का है और हॉस्पिटल बनाने के काम की इत्यादि की कुछ घोशणाएं है जिनको पूरा करवाने की कृपा करें। हसनपुर का नगरपालिका का दर्जा बहाल करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, बाकी आप लिखवा कर भिजवा दें उनको पढ़ा ही मान लिया जायेगा। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बजट पर बोल लेना, दो घण्टे, आपके लीडर बोल कर चले गये। आप भाक प्रस्ताव पर भी बोल चुके है। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि सत्ता पक्ष के जो साथी हैं वे तो सरकार की सराहना ही करेंगे, सरकार को सही रास्ता नहीं दिखायेंगे लेकिन जो विपक्ष के साथी हैं वे पूरी तरह से सही बात कहेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बजट पर बोल लेना। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राधे भयाम भार्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, सही बात कहेंगे तभी रास्ता दिखायेंगे, झुठी बातों से क्या रास्ता दिखायेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने जब डॉ. सीता राम जी को बोलने के लिए कहा तो आपके नेता ने कहा कि यह क्या बोलेंगे ? यह

रिकॉर्ड की बात है। तब आप कुछ बोले ही नहीं। आपके लीडर दो घंटे बोल कर चले गए।

डॉ. सीता राम : अध्यक्ष महोदय, गर्मा गर्मी में ऐसी बातें हो जाती हैं। आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे कहा ही नहीं। (तोर एवं व्यवधान)

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * *

श्री अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड न किया जाये।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा जी से कहना चाहूंगा कि केवल खबरें बनाने के लिए इस तरह की बातें न कहें।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आपके लीडर दो घण्टे बोल कर चले गए लेकिन उन्होंने सरकार की कोई विफलता नहीं बताई (विघ्न)।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्दौरा साहब एक बहुत ही तजुर्बेकार आदमी हैं। सदन के माननीय नेता महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देने के लिए हाउस

में खड़े हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी मन्ता यही है कि आज वाकआउट करके अखबार की खबर बनाना है तो अलग बात है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग केवल अखबार की खबर बनाना चाहते हैं तो अलग बात है वरना इनको बैठकर रिप्लाइ सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप लोग अपनी सीटों पर बैठें और महामहिम गवर्नर साहब के अभिभाषण पर लीडर ऑफ दि हाउस का रिप्लाइ सुनें। डॉ. इन्दौरा इस रिप्लाइ में से आपका जो कुछ भी रह जाएगा वह आप बजट पर बोल लेना। मैं आप अकेले को बजट पर बोलने के लिए आधे घण्टे का समय दे दूंगा अभी आप बैठें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Hon'ble Chief Minister will give reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल किदवई जी ने 7 मार्च, 2008 को जो प्रभावी अभिभाषण दिया, हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए उन्होंने जो बातें कहीं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। इस अभिभाषण में उन्होंने हर मुद्दे को जोड़ा है। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की सरकार की नियति और नीति आज हर गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति, साधारण समाज में पिछड़े हुए हैं। ईमानदारी, मेहनत और नेकनीयत से हमने न केवल अपने वायदों

को पूरा किया है बल्कि जो वायदे नहीं किये थे उससे भी बढ़ कर हमने सारे कार्य किये हैं। स्पीकर सर, तीन साल पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो मेरे साथियों ने एक सपना देखा कि हमने अपने प्रदेश को देश में नम्बर एक का प्रदेश बनाना है और उसके लिए हमने काफी फ़ैसले किये और हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त की। जैसे प्रति व्यक्ति निवेश की बात है जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश में 14वें नम्बर पर था। स्पीकर सर, यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यह सेंट्रल फोरम मॉनिटरिंग ऑफ इण्डिया इकोनोमी ने सर्वे करके कहा है। हम 14वें नम्बर पर थे लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में निवेश के मामले में देश भर में नम्बर वन पर है। (इस समय मेजें थपथाई गईं) स्पीकर सर, इसी प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन में हमारा हरियाणा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश देश भर में दूसरे नम्बर पर है और गोवा से पीछे है। गोवा में टूरिस्ट इन्कम है। इसी प्रकार से हमारा प्रदेश दूध की उत्पादकता में पहले पंजाब से पीछे था आज दूध के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश देश भर में नम्बर वन है। (इस समय मेजें थपथाई गईं) स्पीकर सर, इसी प्रकार से गेहूं के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश भर में नम्बर एक पर है। अध्यक्ष महोदय, तरक्की का जो आधार होता है वे वित्तीय साधन होते हैं। जब तीन साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले वर्ष 2004-05 में हमारी सरकार आने से पहले सरकार को जो बजट था मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा।

हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं जब इनकी सरकार थी तो इनका जो प्लान्ट बजट था 2305 करोड़ रुपये था और इस में से इन्होंने कुल 2108 करोड़ रुपये खर्च किये। स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज वर्ष 2008-09 में हमारा जो प्लान्ट बजट है वह 300% बढ़ गया है। और हमारा प्लान्ट बजट 6650 करोड़ रुपये हो गया है जो कि सरकार की नीयत और नीति का जीता जागता सबूत है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हर पन्ना प्रदेश की खुहाली की कहानी कहता है। उन्होंने कहा कि हर पन्ने में हमारी खुहाली है और प्रदेश में चारों तरफ गहमा-गहमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना में विवास नहीं करता लेकिन मुझे इस बात की हैरानगी है कि जैसे अभी डॉक्टर इन्दौरा साहब भी कह रहे थे और पहले श्री चौटाला जी भी बोल गये। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में बसन्त बहार आ रही है लेकिन मेरे विपक्ष के भाईयों को यह पतझड़ क्यों लग रही है, पता नहीं इसका क्या कारण है। ये लोग सिर्फ सुखियां बनाने के चक्कर में रहते हैं। इन लोगों को तो सरकार के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। इनको चाहिए कि इस बारे में ये कोई पैरामीटर तय करें, यहां हाउस में बैठकर बहस करें और तथ्य सबके सामने रखें तो सारी सच्चाई सामने आएगी लेकिन अखबार की सुखियां बनाने से कुछ नहीं होगा। स्पीकर सर, जैसे हमारे पार्लियामेंट्री अफैयर्स मिनिस्टर ने कहा कि अखबार की सुखियां बनाना ही विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव सलाह देना और सही बात करना होता

है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वच्छ और पारदर्शिता प्रदान किया है इसलिए हम किसी ढोंग या प्रपंच की सहायता नहीं लेते जबकि हमारी साथी लोकहित का जामा पहन कर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, चेहरे पर चेहरा लगाकर ठगने वालों को समझना चाहिए कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। चेहरे पर चेहरा लगाकर सच्चाई छिप नहीं सकती है। वह तो सामने आएगी। सच्चाई नैकेड होती है। This is an untruth must hide behind the clock of curtains. Truth, however, must go naked it. राज्य के लिए सबसे बड़ी चीज है भ्रान्ति और सुरक्षा। यह सब आपके सामने है। आप निवेदन लगाएं। आज किसी प्रकार से हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। यह सब आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रान्त के सभी वर्गों की तरक्की से जुड़े हुए सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कृषि जगत के विकास के बारे में कहना चाहूंगा। इसका विकास करना हमारा धर्म है। वर्ष 2008 का जो केन्द्रीय बजट पेश हुआ है और उसके बारे में मान साहब ने भी कहा है कि यह बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक बजट श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया है। इस बजट में किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ किया गया है यह एक ऐतिहासिक कदम है। आज तक के इतिहास में इस फैसले का कोई मुकाबला नहीं है। मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और श्रीमती सोनिया

गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के साथी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आएंगे लेकिन मुझे नहीं पता वे क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता कि वे किसानों के हितों की बात करते हैं। उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान क्रिटिसिज्म किया है, उन्होंने कहा है कि ऋण माफी की वजह से डिफाल्टर्स बढ़ेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता के द्वारा वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1990 में ऋण माफ किया था उसका गुणगान किया था। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केन्द्र की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने जो ऋण माफ किया है ये इस बारे में हाँ या ना में जवाब दें कि वे उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं। एक तरफ तो ये हक की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुखालफत करते हैं। इसकी यह बात हमारी समझ में नहीं आई है। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सुनील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम ढकोसलों के खिलाफ हैं, जो हकीकत में काम करते हैं उनके खिलाफ नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ढकोसले तो आके सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिफाल्टर्स बढ़ेंगे। (गोर एवं व्यवधान) यह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ब्यान है।

डॉ. सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि इस ऋण माफी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं इनको उन दोनों के बारे में बताना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

Sh. Bhupinder Singh Hooda : I am not yielding.
(गोर एवं व्यवधान) सदन की कुछ गरिमा होनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : When the leader of the House is speaking there should not be any interruption at all.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इनको कुछ तो सुनना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ऋण माफी की स्कीम जो केन्द्र की सरकार ने दी है, ये उसके हक में है या खिलाफ में है। ये हाँ या ना में जवाब दें। इससे सारी बात स्पष्ट हो जायेगी। चौटाला जी जब विपक्ष में थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे और यह बात आम कहते थे और लोगों को गुमराह करते थे कि न मीटर होगा और न रीडिंग ली जाएगी। तुम बिजली के बिल न दो। इनके सत्ता में आने के बाद कण्डेला में जो हुआ वह सब जानते हैं और वहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियां चलवाईं। अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला जी के बारे में कहना चाहूंगा कि —

वायदा तो कर लिया लेकिन यह नहीं सोचा तुमने,

वायदा करना तो आसान है लेकिन वायदे की वफा मुँ कल है।

अध्यक्ष महोदय, जब वे सदन में बोले तो उस समय मैं यहां पर नहीं था लेकिन मुझे यह जरूर पता चला कि उन्होंने क्या बोला है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि -

मेरा जमीर बहुत है मेरी सदा के लिए

तू तो नसीयत न कर खुदा के लिए।

तू क्या नसीयत करेगा खुदा के लिए,

मेरा जमीर है मेरी सदा के लिए।।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी ने जो कर्जे माफ किए थे उसके बारे में इन्होंने सदन में चर्चा की। उस वक्त उन्होंने 34 कराड़े रूपये कर्जे माफ किए गए थे जबकि ये हजारों करोड़ों रूपये के कर्जे माफ किए गए बता रहे थे। मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि उस वक्त 34 करोड़ रूपये का ही लोगों को फायदा हुआ था।
(गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर है। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे पास इनकी कही हुई बात का रिकार्ड है। (Interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : The leader of the House has not yielded.

Dr. Sushil Indora : He is not yielding but the facts are there.

Shri Randeep Singh Surjewala : You were given the opportunity to tell the facts but it does not mean you will continue to speak. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप इस तरह खड़े न हों, आप बैठें।

डॉ. सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं इन्हीं का एक भोर कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही गवर्नर ऐड्रैस पर किया हुआ भाषण है। आप चाहें तो रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए। ये अब 34 करोड़ रुपये की बात कह रहे हैं जबकि इन्होंने ही अपने भाषण में कहा था कि चौधरी देवीलाल जी ने 2830 करोड़ रुपये माफ किए थे। स्पीकर साहब, यह लिखा हुआ है। यह 2005-06 में इनका दिया हुआ भाषण है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक क्लैरीकल मिस्टेक का सहारा ले रहे हैं।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये आज सिर्फ 34 करोड़ रुपये कह रहे हैं जबकि इन्होंने पहले कुछ और कहा है। इन्होंने अपने भाषण में जोर देकर कहा है कि उस समय 2830 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं इसलिए इस बात की भी इन्वेस्टीगेशन करायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बैठें ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऑन दि प्लोर दि हाउस यह नहीं कहा है । इन्दौरा जी मेरे साथ है और ये पार्लियामेंट में भी रहे है । इनको हाउस की गरिमा को बनाए रखना चाहिए । इनको सुनने की सब्र रखनी चाहिए । लोगों ने इनका झूठ बहुत सुन लिया इसलिए अब इनको सच्चाई सुनने की आदत डालनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, इस तथ्य के बारे में एक कमेटी बना दी गयी है । वह कमेटी यही चीज वैरीफाई करेगी । इस कमेटी की मीटिंग 19 तारीख को रख दी है । वहां पर आप अपनी ये बातें कह लेना ।

डॉ. सु गील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही हुई बात कह रहा हूं । मैं सदन के सम्मान का पूरा ध्यान रखता हूं । मैं सदन के नेता का और चेयर का भी सम्मान करता हूं लेकिन जो बात है उसको सामने रखने की जिम्मेवारी मेरी है ।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, सदन के पटल पर दो बातें आयीं हैं । एक तरफ तो चौटाला साहब और आप कह रहे हो और दूसरी तरफ इधर से पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर और सदन के नेता अपनी बात कह रहे है तो उसकी वैरीफिके इन के लिए ही कमेटी की मीटिंग 19 तारीख को बुलाई गई है । वहां पर आप

अपने ऐवीडेंस रखना कि कौन झूठा है और क्या है किसने मान मर्यादा तोड़ी हैं वहां पर पता लग जायेगा। प्लीज, अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, तथ्य सामने है। 1987-88 में किसानों के कर्ज माफ होने से कितना लाभ हुआ है वह मैं आपको बता देता हूं। 34.31 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ है। मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारी सरकार ने तो 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों की माफी योजना की एक स्कीम दी। इस स्कीम में 6,19,137 उपभोक्ता परिवारों को तकरीबन हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जैसा उद्यमान जी ने कहा, सहकारी बैंकों के कर्ज का ब्याज माफ करने के लिए छोटे दुकानदारों एवं कामगारों को 130 करोड़ रुपयों का लाभ पहुंचाने की स्कीम मौजूदा सरकार ने चलायी। इस स्कीम का लाभ भी तकरीबन 3 लाख 64 हजार कर्जदारों ने 450 करोड़ रुपयों का उठाया है। अध्यक्ष महोदय, जो किसान कोऑपरेटिव बैंकों का लोन लते थे और न देने की स्थिति में उनको जीप में बिठाकर ले जाते थे और जेल में रखते थे। जेल में वह जितने दिन रहते थे उतने दिन ही उसकी खायी हुई रोटियों का खर्चा भी उसके कर्ज में जोड़ दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, किसानों की गिरफ्तारी का ऐसा काला कानून था लेकिन इस काले कानून को भी मेरी सरकार ने खत्म कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, माजूदा कांग्रेस सरकार ने सहकारी फसल

ऋणों के ब्याज की दर जो पहले 11 प्रति ात किसानों को देनी होती थी उसको अब 7 प्रति ात कर दिया है। अब सात प्रति ात ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जा रहा है। यह हमारी किसानों के प्रति कटिबद्धता है।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन की मांग तो चार प्रति ात की है इसलिए मुख्यमंत्री जी चार प्रति ात ब्याज की दर की घोशणा करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : लेकिन इनके राज में तो यह ब्याज की दर 11 प्रति ात थी लेकिन हमने यह दर चार प्रति ात तक घटा दी। डॉक्टर साहबखु आप 11 प्रति ात में से 4 प्रति ात दर घटाओं।

डॉ. सु गील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस ब्याज दर को चार प्रति ात पर ले आए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब सदन के नेता बोल रहे हों तो इनको इस तरह से इंटरूप्शन नहीं करनी चाहिए।

डॉ. सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, जब हमारे नेता बोल रहे थे तो ये सारे लोग बड़ी वाहवाही लूटवा रहे थे। यह क्या मामला हुआ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके नेता तो सदन के नेता नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, बड़ी खुशी होती अगर कोई विपक्ष के नेता होते लेकिन इनके तो उतने नम्बर भी नहीं है। हर कोई फ्री फोर आल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप हाउस की गरिमा बनाए रखें क्योंकि सारी कार्यवाही की विडियोग्राफी भी हो रही है। आप हाउस की गरिमा को लांघ रहे हैं। When the leader of the House is on his legs, you should listen patiently. जब आपको बता दिया कि आप आधा घंटा बोल लेना और अभी आप प्वायंट्स नोट कर लें इसलिए अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये तो अपना टेप करके उनको सुनाने की बात कर रहे हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। आपने बहुत सारी झूठी बातें कह लीं हैं अब आप सच्ची बातें सुनने का दम रखो। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2003-04 में जब इन साथियों की सरकार थी तो गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रुपये था और अब हमारे समय में वर्ष 2007-08 में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल रेट है। इस प्रकार इसमें 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया है। इनकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 40 रूपा बढ़ाया था और हमारे कार्यकाल में 775

रूपये किया, इसमें 195 रूपये का इजाफा किया, इनके समय 40 रूपये मात्र का इजाफा हुआ था। इसी प्रकार से सामान्य धान का रेट 550 रूपये था हमने आपने कार्यकाल में बढ़ाकर 695 रूपये किया और इसमें 145 रूपये इजाफा किया। इसी प्रकार से गन्ने का रेट 110 रूपये था जिसे बढ़ाकर 138 रूपये किया और इस प्रकार 28 रूपये रेट बढ़ाया। इसी प्रकार से बाजरे में 95 रूपये, तिलहन में 470 रूपये, जौ में 145 रूपये, चने में 375 रूपये, कपास में 105 रूपये और सरसों में 200 रूपये का इजाफा किया। यह आपके समक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैं साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो भूमि अधिग्रहण की बाज हुई है। इनकी सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 50 हजार रूपये से लेकर 2 लाख रूपये मिलता था। आज ही इस बारे में जैसा कि क्वै चन ऑवर में बताया गया। हमारी सरकार ने 20 लाख रूपये, 16 लाख रूपये पर एकड़ स्थान के अनुसार सोलेंटियम के साथ लाभ दिया। 26 लाख, 20.80 लाख रूपये पर एकड़ व 10.40 लाख रूपये पर एकड़ मुआवजा दिया। इसके अलावा जो भी सरकारी काम के लिए जमीन अधिग्रहण होगी उसको 15 हजार रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल तक देंगे और हर साल उसमें 500 रूपये की बढ़ौत्तरी देंगे। एस.ई.जेड. के इनके समय में सैकान 4 और सैकान 6 में नोटिस हुए थे, उसमें अब हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि कोई भी जमीन अधिग्रहण होगी तो उसका 33 साल तक 30 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मुआवजा किसान

को देंगे और उसमें 1 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इजाफा होगा। इस बारे में हमारे एक ही फैसले से किसान को कितना लाभ हुआ है, यह आपको बताना चाहूंगा। कुण्डली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे का जो मेरी सरकार की कैबिनेट का फैसला हुआ था उस फैसले की कॉपी मेरे पास है। इसमें लिखा है कि – “The cost of land acquisition is expected to be Rs. 170.80 crores. “ About 3450 acres of land जो जमीन इन्होंने ऐक्वायर की थी उसका कुल मुआवजा 167 करोड़ रुपये उस समय आंका गया था, यह सरकारी पत्र में लिखा है और हमारी सरकार ने आते ही उसका जो फ्लोर रेट फिक्स किया उससे उनको 630 करोड़ रुपये की राशि मिली। इस प्रकार किसानों को सरकार के एक ही फैसले से 500 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इनके राम में किसानों को और गरीबों को लूटा गया था। (गोर एवं व्यवधान) प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंचाई की बात कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने नहरी पानी की कमी की चर्चा की और हमने उस कमी को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में बहुत सारी नहरी पानी की परियोजनाएं चलाई। जिनके बारे में अलग-अलग चर्चा भी हुई है। एक हांसी-बुटाना लिंक नहर है जिसका मकसद यह है कि जो पानी उपलब्ध है उसका समान बंटवारा किया जाए ताकि जिसका जितना हक है उसको उतना पानी मिले। उस नहर का 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और उसके पूरा हो जाने के बाद 2 हजार क्यूबिक पानी उस नहर में आएगा और उसकी लागत 354 करोड़ रुपये के करीब थी और ये साथी कहने लगे

कि जब तक यह बनकर तैयार होगी, इसकी इतनी ही लागत और हो जाएगी। जब 98 प्रतिशत काम अगर पूरा हो गया है तो लागत और बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। इस नहर को बनाने की बड़े जोर-शोर से मुखालफत हुई और काफी कुछ कहा गया। एक पेपर की कटिंग मेरे पास जिसमें लिखा है कि 'नई नहर खोदने से आंतरिक गृहयुद्ध छिड़त्र जायेगा, अजय'। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पानी के समान बंटवारे की बात हो रही है और यह कह रहे हैं कि गृहयुद्ध छिड़ जायेगा। अगर इंसाफ पर गृह युद्ध होना है तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्या आप नहर बनाने के हक में हैं या खिलाफ है, स्पष्ट करें। इस बात का जवाब ये अपने आप दे दें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(श्री ओम प्रकाश चौटाला)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर इस सदन को गुमराह करने का काम किया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप इस नहर के बनाने के हक में हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, गुमराह तो ये आपने आप करते रहे हैं।

श्री ओम प्रकार चौटाला : आप मेरी बात सुनिये, आप बैठ जाईये ।

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन क्या है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हांसी-बुटाना लिंक नहर की बात हो रही है, ये हां या ना में जवाब दें ।

श्री ओम प्रकार चौटाला : आप सुनने की कोशिश तो कीजिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी तो इस बात की है कि न तो हमें बोलने दिया जाता है (विध्न) अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए । (विध्न)

Mr. Speaker : Chautala ji, you are on your legs for personal explanation. What is your personal explanation ? (Noise and Interruptions). Why you are wasting the time of the House ? (Noise and Interruptions).

श्री ओम प्रकार चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे डांट रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं । लीडर ऑफ दि हाउस ने हाउस को गुमराह किया है कि हमारी सरकार के वक्त में 5, 10 या 15 हजार से दो लाख रूपये तक का मुआवजा दिया । यह तो रिकॉर्ड की बात है । अब तक हमारी सरकार ने लोगों को जमीन का कम्पेंसेशन दिया उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त में गुड़गांव के चार गांव की जमीन का

कम्पैसे 1 न 29 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया गया था। भाव किसानों को तब दिए जाते हैं जब जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो किसानों को भी उसी हिसाब से कम्पैसे 1 न दिया जाता है। जमीन के भाव के मुताबिक किसानों को भाव मिलेगा। दूसरा इन्होंने नहर बनाने का जिक्र करने का काम किया। (विधन)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से श्री चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पास इनकी सरकार के समय की कैबिनेट मीटिंग का सबूत है इनकी सरकार के समय में के.एम.पी. एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए 3450 एकड़ जमीन की कीमत किसानों को 170 करोड़ रूपये दी गई। इन्होंने लिखकर दिया हुआ है। जबकि हमारी सरकार ने उसी जमीन का किसानों को कम्पैसे 1 न 630 करोड़ रूपये दिया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है आप भी सबूत के आधार पर कह रहे होंगे, मैं भी सबूत के आधार पर कह रहा हूँ कि कीमतें बढ़ने के बाद कम्पैसे 1 न भी बढ़ जाता है यह स्वाभाविक है। (विधन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : एक दिन में 500 करोड़ रुपये बढ़ गये क्या ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अरे, आप सुनने की हिम्मत तो रखो। कभी एक सदस्य खड़ा होता है कभी दूसरा खड़ा हो जाता है। कोई बिना बोले बोलना भुरु कर देता है (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने अच्छे काम किए हैं उनके लिए हमें चौटाला जी से और उनकी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आज हरियाणा ही नहीं सारा देश इनकी वाह-वाह कर रहा है। जहां तक चौटाला जी का सवाल है इनकी पार्टी का जो नियम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक दफा इनकी पार्टी की मीटिंग हो रही थी जिसमें बड़े-बड़े नेता थे मैं उनके नाम नहीं लेना चाहिता। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब का प्वायंट ऑफ ऑर्डर किस बात के लिए हो रहा है ? (विधन) ये मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब दें न कि हमारी पार्टी के बारे में बताये। ये हमारी पार्टी के आंतरिक मामले में दखल न दें। स्पीकर सर, ये क्या कहना चाहते हैं ? यह स्पष्ट बतायें कि हमारी पार्टी के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की उलूल-जलूल

बात करके ये सदन को क्यों गुमराह करना चाहते हैं। ये क्यों सदन का टाईम खराब कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I am standing on a point of order. (Noise and Interruptions). ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते। Speaker Sir, I want your protection. (Noise and Interruptions). अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी बात है। इनकी पार्टी का नियम यह है कि लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है।

डॉ. सु गील इन्दौरा : स्पीकर सर, इलाल साहब, हमारी पार्टी के नियमों के ज्ञाता कब से हो गये ? (गोर एवं व्यवधान) इनको अपनी पार्टी की चिन्ती होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी के बारे में क्या बात कर रहे हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत चौटाला साहब और इनकी पार्टी के विधायकों को यह कहना चाहता हूँ कि जो इनकी पार्टी के नियम है कि लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कहते हैं कि लोगों को तो बहकाने की जरूरत है। ये तो लोगों को बहकाने में लगे रहते हैं। सदन के अन्दर और सदन के बाहर इनको बाज आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये।

16.00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने स्पष्ट कहा है कि कुण्डली मानेसर एक्सप्रेस हाइवे के लिए 3450 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, हमारे पास मंत्रीमंडल की बैठक की प्रोसीडिंग्स मौजूद है, जिसको मुख्यमंत्री महोदय जी ने पढ़कर सुनाया है उसमें स्पष्ट है कि कैबिनेट ने यह कहा है कि 170 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा उसके जवाब में माननीय चौटाला जी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है कि कीमतें बढ़ने के साथ-साथ जमीन की कीमतें और मुआवजे बढ़ जाते हैं। भायद वे समझ नहीं पाए और भायद हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाते क्योंकि अध्यक्ष महोदय, कई बार वेवलेंथ नहीं मिलता। उनको मैं यह बताना चाहता हूँ कि उसी 3450 एकड़ जमीन जिसकी कीमत आपने दफा 4 और 6 लगाकर 170 करोड़ रुपये आंकी थी हमारी फ्लोर रेट नीति तय होने के बाद उसकी कीमत 650 करोड़ रुपये हो गई और 500 करोड़ का उसमें इजाफा हुआ, इसलिए सदन को गुमराह न करें साफ बताएं कि आप हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में है या हांसी बुटाना लिंक नहर के लिखाफ है। आप हर बार बात को घुमा लेते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ये बात मान रहे हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो कम्पनसेशन बढ़ता है। 2005 तक तो कीमतें बढ़ी नहीं और हमारी सरकार आते ही कैसे कीमतें बढ़ गई, हमने कीमतें बढ़वाई। हमने

पलोर रेट तय किए और जब पलोर रेट तय किए तो उसके हिसाब से 500 करोड़ रुपये का एकदम इजाफा हो गया, इन्होंने कभी कोर्नर नहीं की।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इनकी सरकार ने किसानों को लूटा, हमने किसानों को आबाद किया है और हमने किसानों को पूरा कम्पनसेशन दिया है। सीधी सी बात है और कोई लम्बी चौड़ी बात थोड़े ही है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बरसों के बाद कीमतें बढ़ी है और मुझे तथ्यों पर आधारित कोई बात कहने में कोई संकोच नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे। चौटाला जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम सम्मान से आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में है या उसके खिलाफ हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी का अमर उजाला में ब्यान आया है कि हांसी बुटाना लिंक नहर की जरूरत नहीं — चौटाला। यह ब्यान इनका सेशन के दौरान आया है।

श्री अध्यक्ष : इनके तो पता नहीं क्या-क्या ब्यान आ रहे हैं, इन्होंने तो विधान सभा के रिकॉर्ड में कह रखा है कि मैं जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा और आज ये इधन बैठे हैं तो पता नहीं ये बैठे हैं या इनका भूत इधर बैठा है। (गौर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के बारे में सदन में चर्चा कर रहा था। मैंने एक सवाल माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने रखा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका ये हां या ना में जवाब दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बैठो, मैं जवाब देता हूँ। (गौर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अमर उजाला में ओम प्रकाश चौटाला जी का ब्यान छपा है कि — हांसी बुटाना लिंक नहर की जरूरत नहीं है, चौटाला। (गौर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कौन चौटाला। (गौर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : ओम प्रका 1 चौटाला का यह ब्यान है। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सीता राम : ***** (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका 1 चौटाला : ***** (गोर एवं व्यवधान)

डॉ. सु गील कुमार इन्दौरा : ***** (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी इस बात का जवाब दे दें कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्षधर है या नहीं हैं। (गोर एवं व्यवधान) दूसरा ये स्पष्ट जवाब दें कि इनके पुत्र ने यह ब्यान दिया था या नहीं दिया कि यदि हांसी बुटाना लिंक नहर बनेगी तो वे हरियाणा में गृह युद्ध करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हमें 11 हरियाणा प्रांत के लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका 1 चौटाला : ***** (गोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। आप सदन के नेता को कैसे कह सकते हैं कि आप बैठो। (तोर एवं व्यवधान) How did you dare to talk like that. (Interruptions) You are doing knowingly when the matter is behind the shadow of your mental impotency.

डॉ. सीता राम : ***** (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please sit down. Nothing is to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ***** (तोर एवं व्यवधान)

डॉ. सीता राम : ***** (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I warn you.

डॉ. सीता राम : ***** (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I name you. You may leave the House (Interruptions)

(At this stage Dr. Sita Ram withdrew from the House)

वाक-आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ऐ प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक-आऊट कर गए।)

श्री राम कुमार गौतम (नारनौद) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बगल में बैठे ये वे लोग हैं जिन्होंने पोलिटिकल आदमियों की छवि को धूल में मिला दिया। ये लोग प्रदेश की जनता का खरबों रुपये लूटकर खा गए। आपकी सी.बी.आई. ने जाने कहां सो रही है ? अगर सी.बी.आई. इनके खिलाफ जल्दी से कार्यवाही करती तो आज ये यहां न होते। इन लोगों ने पोलिटिकल लोगों की ऐसी छवि बना दी कि सभी पोलिटिकल लोगों को जनता ठग समझने लगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये लोग जो प्रदेश का खरबों रुपया खा गये इनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार के स्तर पर ढिलाई क्यों बरती जा रही है। इस प्रकार के ठग और लुटेरे लोगों को तो यहां आने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। इनकी सारी की सारी जायदाद कुर्क करके इनको जेल के अन्दर डालना चाहिए। ऐसे-ऐसे ठगों की वजह से ही आम आदमी के मन में राजनीतिज्ञों की ऐसी छवि बन गई है कि सभी पोलिटिकल आदमी ठग और बदमाश होते हैं। ये तो सदन में आकर भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे इनके लिए न तो कोई कायदा है और न ही कोई कानून है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह अनुरोध करूंगा कि वे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर
मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आवासन देना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि हमारी चक्की आहिस्ता पीस रही है लेकिन वह बारीक पीस रही है। इस बात की वे कोई चिंता न करें।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहले हरियाणा प्रदेश में पानी का न्यायोचित बंटवारा नहीं था। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बात का पक्का इरादा किया है कि हम अंतिम छोर तक पानी पहुंचायेगें। जिसका जितना हक बनता है वह उसको मिलेगा। इसी प्रकार से जो भाहबाद-दादुपुर-नलवी परियोजना है वह पिछले 20 वर्षों से कागजों में थी। यहां पर जितनी भी अब तक असैम्बली बनी उनमें से हरेक असैम्बली में प्रत्येक आदमी ने इस बात की चर्चा की लेकिन फिर भी 20 वर्षों तक वह कागजों में ही घूमती रही। यह कार्य भी हमारी सरकार ने भुरु किया। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस नहर का 68 प्रतिशत अर्थवर्क का काम और 30 प्रतिशत पक्के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। इस पूरी परियोजना में कम्पलीट होने पर 267 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार से ओटू झील के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 55 करोड़ रुपये की लागत से ओटू झील की खुदाई का कार्य भुरु करवाया है और इससे

सिरसा जिले में 5 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई में लाभ होगा। इसके साथ ही साथ हम वर्ष 2008-09 के दौरान 81 करोड़ की लागत से सभी नहरी खालों की मरम्मत का कार्य पूरा करेंगे। इसके अलावा जो एस.वाई.एल. नहर है यह हमारी लाईफलाइन है इसके निर्माण और इसमें अपने हिस्से का पूरा पानी लाने के लिए भी हम वचनबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के आदेश पारित किए हैं। आज हमारे सामने सबसे अहम मसला और सबसे बड़ी समस्या बिजली की कमी की है। यह समस्या हमें विरासत में मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार हम निरंतर विकास कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण हमारी बिजली की मांग भी दिन प्रति दिन हर साल बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से यह मांग बढ़ रही है उस हिसाब से बिजली के उत्पादन की व्यवस्था पिछली सरकारों ने नहीं की। मैं किसी की निन्दा करने का आदि नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश को अस्तित्व में आये 40 साल हो गये हैं और कुछ लोग 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे लेकिन मांग के अनुसार बिजली को बढ़ाने के लिए किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किये। आज हम 1587 मैगावाट बिजली पैदा करते हैं और दो हजार मैगावाट के आस पास बाहर की बिजली परियोजनाओं में हमारा हिस्सा है। इस प्रकार इस समय हमारे पास कुल उपलब्ध बिजली 4051 मैगावाट या इससे कुछ अधिक है। इसीलिए जब 3 साल पहले हमारी

सरकार बनी तो हमने लोगों से वायदा किया था कि हम 5000 मैगावाट और बिजली पैदा करेंगे क्योंकि वर्ष 2010 में बिजली की मांग कम से कम 8500 मैगावाट होने जा रही है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिजली विकास की धुरी है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथ अपने चुनाव घोशणा पत्रों में यह वायदे करते थे कि फलां तारीख से हम 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन उन द्वारा निर्धारित तारीख कभी आई ही नहीं। ऐसा करके ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते रहे। अध्यक्ष माहदेय, मैं इस बारे में आपको थोड़ा कम्पैरेटिवली बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 में 578 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली उपलब्ध थी और उसके मुकाबले में वर्ष 2006-07 में हमने 662 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली उपलब्ध कराई और जनवरी 2007-08 में 739 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से भी बिजली की खरीद की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में जो बिजली भाार्ट टर्म प्रॉवीजन के तहत खरीदी गई इनकी सरकार के समय में उस पर 607.15 करोड़ रुपये खर्च किये गये उसके मुकाबले वर्ष 2007-08 में हमने 1583.71 करोड़ रुपये की बिजली की खरीद बाहर से की गई। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा बाहर से बिजली की खरीद में भी बड़ी भारी बढ़ोत्तरी की गई। इनकी सरकार के समय में पांच साल में कुल 4095 करोड़ रुपये बिजली पर खर्च किये गये और हमारी सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में इस मद पर 6748 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी व बिजली कम्पनियों द्वारा 25,520 करोड़ रुपये बिजली के उत्पादन पर खर्च किये जायेंगे। इसी प्रकार से मैं यमुनानगर थर्मल प्लांट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार का 5000 मैगावाट अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। यमुनानगर में बिजली का प्लांट लगने के बारे में भी हम सुनते रहे। आज यमुनानगर में बिजली का प्लांट लग गया है। इस प्लांट को लगाने के लिए कई बार िालान्यास किया गया है और मार्च 2008 में कोयले से 300 मैगावाट की पहली यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। अब तक 85 लाख यूनिट बिजली नई यूनिट से बनाई जा चुकी है और इसकी दूसरी यूनिट अप्रैल या मई, 2008 में शुरू होने वाली है। इस पर लगभग 2400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यमुनानगर में बिजली उत्पादन में देरी की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जुलाई, 1998 में तत्कालीन बंसी लाल सरकार ने बिजलीघर लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1999 में चौटाला जी लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गये और इन्होंने इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया। जुलाई, 1998 से 6 वर्षों के बाद 30 सितम्बर, 2004 को, चुनाव से ठीक पहले चौटाला सरकार ने रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड को बिजलीघर निर्माण की चिट्ठी दी। 6 महीने तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। हमने यह कार्य शुरू करवाया और इसे पूरा भी करवाया। इस प्रकार से सबसे कम समय में यह कार्य पूरा हुआ है। इसी प्रकार से राजीव

गांधी थर्मल प्लांट हिसार के खेदड़ में हम लगाने जा रहे हैं जिस पर 3775 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। उस पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट झाड़ली (झज्जर) में 1500 मैगावाट का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। उस पर 7892 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और उस पर भी कार्य चल रहा है। उसमें 750 मैगावाट बिजली हरियाणा का हिस्सा होगा। दूसरा, झाडत्रली में ही 1200 मैगावाट का प्लांट लगाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जायेगी और जल्द ही उसका काम भुरु होने जा रहा है। 2000 मैगावाट बिजली की खरीद की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर ली जायेगी। अमर कंटक प्रोजैक्ट 2 में से 300 मैगावाट बिजली हमें मिलेगी। इसी तरह से बुडील हाईड्रो प्रोजैक्ट से 70 मैगावाट बिजली 2010 तक हमारे को उपलब्ध हो जायेगी। राजीव गांधी ग्रामीण बिद्युतीकरण योजना के तहत अब तक कुल 200 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2,32,000 परिवारों को इसका लाभ हुआ है। नॉन कन्वैन्शनल एनर्जी पर भी हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। 705 मैगावाट बिजली के उत्पादन का हम समझौता कर चुके हैं और 2 साल में बिजली उत्पादन की सम्भावना है और इस पर लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। हमारा पूरा ध्यान बिजली उत्पादन की तरफ है। मानसून 217.96 करोड़ यूनिट बिजली प्रान्त को दी है जो कि पिछले साल के मुकाबले 11.14 प्रति सैत अधिक है। गैस उपलब्ध ने होने के बावजूद गैस आधारित बिजलीघर के िालान्यास के बारे में गेल द्वारा गैस सप्लाई करने के आवासन

पर फैसला किया गया लेकिन गैस अब तक उपलब्ध नहीं हुई। गैस उपलब्ध होते ही वह कार्य भुरू हो जायेगा। एक बात और की गई और विपक्ष की तरफ से बयान भी आया, इन्होंने अपने भाषण में भी चण्डीगढ़ हवाई अड्डे के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को गर्व से कहना है कि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और यहां पर मोहाली में नाम से हवाई अड्डा बनने जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उस हवाई अड्डे में पंजाब हिस्सेदारी करे तो यह लाभदायक और हरियाणा हिस्सेदारी करे तो वह नुकसानदायक कैसे हो सकता है मुझे इस बात का गर्व है कि अगर हम यह समझौता नहीं करते तो चण्डीगढ़ पर हमारा क्लेम कमजोर हो सकता था। लेकिन चौटाला जी तो चाहते हैं कि चण्डीगढ़ को पंजाब में ही मिला दिया जाये क्योंकि वहां उनके साथ बादल की दोस्ती है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे हरियाणा में इस बात की प्रतीक्षा हुई कि हरियाणा ने इसमें अपना हिस्सा लिया। (इस समय मेजें थपथपाई गई) आखरी मिनटों में हमने फैसला किया कि जब तक हमारा हिस्सा तय नहीं हो जाता तब तक हम समझौता नहीं होने देंगे क्योंकि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। केन्द्र की टीम को हमने हवाई अड्डे पर ही रोका। इनको इस बात की निन्दा करने की बजाय प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह एक कमर्शियल प्रोजैक्ट है और इसमें हमारे को लाभ ही होगा। हरियाणा को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यहां विकास होगा। हमारा प्रदेश चण्डीगढ़ के चारों तरफ है। चण्डीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है हम सोचते हैं कि

इसमें हम साझीदार हों, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें 51 प्रतिशत भाग भोयल भारत सरकार का होगा जब कि 24.5 प्रतिशत भाग हरियाणा सरकार का और 24.5 भाग पंजाब सरकार का होगा। इसमें पंजाब सरकार तथा हरियाणा सरकार बराबर के हिस्सेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि विकास के नाम पर गुंडगांव हमारा एक किस्म से प्रेस्टिजीयस फेस बना हुआ है और पूरी दुनिया में गुंडगांव का नाम की चर्चा है और इसको हम मेट्रो रेल सेवाएं पहुंचाने की मंजूरी भी दे दी गई है और बहादुरगढ़ तक यह मेट्रो सेवा पहुंचाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे विकास कार्यों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है जो कि सड़कों और पुलों से कन्सर्ड है। इनके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है इसलिए हमने सड़कों और पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 2007-08 में ही 450 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मंजूर करवाए हैं जिसमें से 1085 किलोमीटर लम्बी और 108 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जा रहा है। स्पीकर सर, हमने 28 नवम्बर, 2007 को 3000 हजार करोड़ से राजीव गांधी ब्रिजिज एण्ड रोड डिवैल्पमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है इसके अन्तर्गत हर वर्ष 1000 करोड़ रुपये इस कार्य पर खर्च करेंगे। रेलवे ओवर ब्रिजिज पर सरकार ने रिकॉर्ड काम किया है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और 1966 से लेकर 2005 तक केवल 16 आर.ओ.बी. का निर्माण हरियाणा में हुआ है जबकि मौजूदा सरकार के तीन

साल के कार्यकाल में 4 आर.ओ.बी. तो पूरे कर लिये गये हैं और 20 आर.ओ.बी. पर 300 करोड़ रुपये की लागत से काम चालू हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में ही 24 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य भुरू हो गया है (इस समय मेजें थपथपाई गईं) जब कि 40 साल के कुल 16 आर.ओ.बी. बने हैं। अध्यक्ष महोदय, 85 पुलों के लिए 82 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और इसके साथ ही 139 पुलों का, 110 करोड़ रुपये की लागत से सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्पीकर सर, दिल्ली-रोहतक हाई-वे की सिक्स लेनिंग का काम भुरू है और पानीपत में ऐलिवेटिड कॉरीडोर सड़क लगभग सम्पूर्ण हो चुकी है। दिल्ली-बदरपुर फ्लाईओवर के काम की मन्जूरी हो चुकी है जो हमारी सरकार के लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि आज जो हमारा हरियाणा है इसमें किसान की जमीन बहुत ही थोड़ी रह गई है। अगर दादा के नाम पर दस एकड़ जमीन से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हम रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा नहीं करेंगे तो प्रदेश में अराजकता पैदा हो जायेगी। अगर हम रोजगार के साधन बढ़ाने की कोई गुंजाई नहीं रही है क्योंकि किसान आज दस एकड़ से आधार एकड़ पर पहुंच गया। यही कारण है कि हम प्रदेश में इण्डस्ट्रलाईजेसन

पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम एग्री से इण्डस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़ी भारी चर्चा की कि सरकार ने एस.ई.जैड. के लिए जमीन ऐक्वायर की है जबकि इन्होंने खुद अपनी सरकार के कार्यकाल में सेज के लिए जमीन ऐक्वायर की थी। जब हम इण्डस्ट्रिलाईजे टान की ओर जा रहे हैं और लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि उद्योगों में जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर हमने लोगों को रोजगार देना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और इण्डस्ट्रीज अगर लगेंगी ओर कोई बड़ी यूनिट लगती है तो छोटे-छोटे कई यूनिट्स लगेंगे और जो कोई काबिल बच्चा होगा वह अपना छोटा यूनिट लगाएगा और कोई बच्चा इस छोटे या बड़े यूनिट में नौकरी करेगा या अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा करेगा। इसी प्रकार से सभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। दूसरे हिसाब से हमने इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। स्पीकर साहब, लागत में हम आज प्रथम स्थान पर हैं। हरियाणा के 40 साल के इतिहास में इण्डस्ट्रीज में कुल निवे 1 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद के तीन सालों में इण्डस्ट्रीज के अन्दर निवे 1 33 हजार करोड़ रुपये ऑन ग्राउन्ड हो गया है। मुझे इस बारे में सदन में बताते हुए खुशी हो रही है। इसके साथ ही 68 हजार करोड़ रुपये का निवे 1 इण्डस्ट्रीज का पाईप

लाईन में है। जो एस.ई.जैड. का निवे 1 है वह इससे अलग है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि क्षेत्र का भी ध्यान है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बातना चाहूंगा कि हमारा यह फैसला है कि हमारी हरियाणा की जितनी भी भूमि है उसके 1 प्रति 10 पर ही इण्डस्ट्रलाईजे 10 न होगी, उससे ज्यादा पर हम इण्डस्ट्रलाईजे 10 न नहीं करेंगे। इससे ज्यादा पर न इण्डस्ट्रलाईजे 10 न हा सकती है और नही हम करेंगे। इस 1 प्रति 10 जमीन पर हम रोजगार के साधन भी पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि एस.ई.जैड. में 93 प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे जिसमें से 53 प्रस्तावों को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 2 करोड़ का इन्वैस्टमेंट अनुमानित है। इसमें 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा हम नए इण्डस्ट्रियल ईल्ड खरखौदा, रोहतक, फरीदाबाद, और यमुनानगर में बना रहे है। हम चार आई.एम.टी. की स्थापना भी करने जा रहे है। इण्डियन ऑयल कारपोरे 10 के द्वारा पानीपत में पेट्रो कैमिकल हब भी बना रहे है जिसमें कुल 35,000 करोड़ रुपये का निवे 1 होगा। वहां पर 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का भी हमें भरोसा है। इसीतरह से अध्यक्ष महोदय, 1900 करोड़ रुपये की लागत से के.एम.पी.ई. एक्प्रेस हाई-वे के बारे में भी चर्चा हुई है। इसी तरह से हम 135 किलोमीटर लम्बे इकोनौमी हब की भी बात कर रहे हैं। हम असको नॉबेल कॉरीडोर के रूप में डिवैल्प करना चाहते है। इसके बारे में मैंने कहा है कि आज इसका कुल कम्पनसे 10 167

करोड़ रुपये उस समय किसानों का आंका गया था लेकिन आज हमने किसानों को उसके 630 करोड़ रुपये दिलवाए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने किसानों को लगभग 500 करोड़ रुपये का लाभ दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा देा में पहला प्रदेा है जिसने श्रमिक कल्याण के लिए अपनी श्रमिक नीति बनाई है और न्यूनतम वेजिज के रूप में 3510 रुपये प्रति माह के दिए जा रहे हैं। इसमें हम सब प्रदेाों से ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, िाक्षा का जहां तक सवा है तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आगे जिस प्रकार से दुनिया छोटी होती जा रही है उस हिसाब से आगे वही देा कम्पीटिा न में जाएगा जो िाक्षा में आगे होगा। अगर िाक्षा में हम पिछड़ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविश्य उज्ज्वल नहीं होगा। इस वास्ते िाक्षा पर हमारी सरकार खास ध्यान दे रही है। इसमें मैं यह कह सकता हूं कि 3 सालों में हमने िाक्षा के बजट में 200 गुणा इजाफा किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में िाक्षा के लिए कुल 1622.89 करोड़ रुपये का बजट में प्रोवीजन था और उसके मुकाबले में वर्ष 2008-09 में हमारा प्रस्तावित बजट 3129 करोड़ रुपये का है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) उन 25 प्रतिात बच्चों में से 5 प्रतिात बच्चों की फुल फी कन्सेा न होगी। 10 प्रतिात बच्चों को 50 प्रतिात फी कन्सैा न होगी ताकि गरीबों से लेकर मिडल क्लास तक और अमीरों के बच्चें भी वहां पर अच्छी उच्च िाक्षा प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी िाक्षा का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो। इसी तरह से

हमने हरियाणा में बजुसैट की स्थापना की है। अध्यक्ष महोदय, पूरे एरिया में हमने शिक्षा में सबसे बड़ा नेटवर्क इन्ट्रोड्यूज किया है। आज 11,000 कॉलेजिज को एजुसैट से जोड़ा गया है ताकि हमारे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां स्कूलों में सैमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है इसका हमें लाभ भी मिला है। इससे स्कूलों में बच्चों की और टीचर्स की हाजिरी में इजाफा हुआ है। इसी तरह से नये अध्यापकों की भी भर्ती हुई है। शिक्षकों की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। इस तरह का आरक्षण करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि तीन वर्षों में चाहे टैक्नीकल ऐजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे कोई और टैक्नीकल ऐजुकेशन हो या चाहे पोलिटैक्निक की बात हो, बहुत रोजगार के साधन इस लाइन में उपलब्ध होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों में 31 नये आई.टी.आई. 5 नये पोलिटैक्निक कॉलेज की स्थापना की गयी है। जब हमारी सरकार आयी थी उस समय तकनीकी संस्थाओं से सीटों की संख्या 24 हजार थी लेकिन हमारी सरकार ने तीन वर्ष में इनको बढ़ाकर 52 हजार कर दिया है और आने वाले दो सालों में हम इनकी संख्या एक लाख करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जो हमारा गरीब और दबा हुआ वर्ग है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हमने बजट में बड़ी भारी वृद्धि की है। इसके मुकाबले में अगर मैं पिछली सरकार के बजट का जिक्र

करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में सामाजिक न्याय एवं सवित्तकरण के बजट में कितना प्रावधान था वह मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दौरान 40.94 करोड़ रूपये रखे गए थे जबकि अब वर्ष 2008-09 में हमने 697 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए हैं यानी कई गुणा इसमें ज्यादा पैसा दिया गया है ताकि इसका लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमने बजट में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। वर्ष 2003-04 में इसके लिए कुल 47.40 लाख रूपये के बजट का प्रावधान था जबकि अब 2008-09 में प्रस्तावित बजट में इसको बढ़ाकर 2006.43 करोड़ रूपये करने का हमारा प्रस्ताव है। सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए, बी.पी.एल. परिवारों के लिए, गरीब आदमियों के लिए 100-100 वर्ग गज के प्लॉट्स देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, जो पहले प्लॉट्स बंटे थे उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं गांवों में जाता था तो हमने देखा कि बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे अलाट हुए थे जिनका कब्जा लोगों ने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कोई प्लॉट बहुत गहराई में और कोई जोहड़ में काट दिया था जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन अब हमने फैसला किया है कि जो ये सौ गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे वह पूरी तरह से डिवैल्प करके दिए जाएंगे। इनमें वहां पर पानी का भी इंतजाम होगा, सड़कें भी होंगी और बिजली भी होगी। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के पहली से बारहवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले

लड़के-लड़कियों को सौ रूपये से लेकर चार सौ रूपये मासिक वजीफे देने की भी एक स्कीम है। एक से लेकर पांचवीं कक्षा तक के लड़के को सौ रूपये लड़की को 150 रूपये, पांचवीं कक्षा कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के लड़के को 150 रूपये, लड़की को दो सौ रूपये देने का फैसला किया गया है। इस प्रकार से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 280 करोड़ रूपये का एक पैकेज दिया जा रहा है। इस पैकेज में अनुसूचित जातियों के पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को किताबें और वर्क्स बुक्स मुफ्त में दी जाएंगी। इसके अलावा स्कूल की वर्दी, स्टेनरी, जूते आदि के लिए वर्ष में एक बार वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकारी पोलिटैक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के बच्चों की ट्यूशन फी का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तरह अनुसूचित जाति के 8 लाख परिवारों को जो हरियाणा में है, मुफ्त में कनेक्टिंव देने का फैसला किया गया है। खाली कनेक्टिंव ही नहीं बल्कि 200 लीटर की एक टंकी और एक टूटी भी मुफ्त में उनको देने का फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक तीन लाख से अधिक कनेक्टिंव दिए जा चुके हैं और बाकि कनेक्टिंव भी हम देने जा रहे हैं। बी.पी.एल. में अनुसूचित जाति एवं टपरीवास जाति को मकान बनाने की राशि जो पहले दस हजार रूपये थी, उसको बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया गया है। इसी तरह से इनके मकानों की मरम्मत

के लिए दस हजार रुपये देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह से गांवों में अनुसूचित जाति के 11 हजार कर्मचारी लगाने का भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है और बहुत सारे कर्मचारी लग भी चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 50 प्रति गांव से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले भाहर के वार्ड को एक करोड़ रुपये का विकास अनुदान देने का फैसला भी किया गया है। 50 प्रति गांव से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांव को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम योजना के तहत 50 लाख रुपये डिवैल्पमेंट ग्रांट देने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी विवाह भागुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 15 हजार रुपये का भागुण कन्यादान के रूप में देने का प्रावधान है। इससे अब तक 45339 परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त अब हमारा ध्यान आम आदमी के स्वास्थ्य की तरफ है। आमतौर पर स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यदि लोग स्वस्थ होंगे तो ही हमारा प्रदेश प्रगति कर सकता है। तीन वर्षों में इस मद में हमने लगभग 100 प्रति गांव वृद्धि की है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है उस मामले में हरियाणा देश में दूसरे नम्बर पर है। इस समय राज्य में सात नये अस्पताओं का निर्माण, पांच नयी एस.एच.सी., 40 पी.एच.सी. और पांच सब सेंट्रों का निर्माण किया जा रहा है। रिवाड़ी, अम्बाला और यमुनानगर में ट्रोमा सेंट्रों का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 740 करोड़ रुपये का

दूसरा चरण भुरु हो चुका है। 475 नये प्रसूति गृह स्थापित किए गए हैं जिसमें लगभग 400775 बच्चों का जन्म हुआ है। वहीं पिछले मृत्यु दर 62 प्रति हज़ार से घटकर 42 प्रति हज़ार रह गई है। स्त्री पुरुष अनुपात वर्ष 2001 के 819 की तुलना में नवम्बर, 2007 में 860 तक पहुंच गया है। इस प्रकार लड़का लड़की अनुपात को ठीक करने के लिए भुरु की गई लोकप्रिय लाडली योजना के तहत 63532 परिवारों को इसका लाभ हुआ है। महिला कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु लड़कियों के लिए 25 प्रति हज़ार आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए मकानों में महिलाओं के लिए 33 प्रति हज़ार आरक्षण किया है। शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रति हज़ार आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं के नाम सम्पत्ति की रजिस्ट्र करने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रति हज़ार की छूट दी है। रक्षा बंधन पर हरियाणा रोड़वेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। महिलाओं के नाम पर यदि बिजली का कनेक्शन लिया जाता है तो प्रति यूनिट पर दस पैसे छूट की सुविधा दी है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा विकलांग पेंशन 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह की है। बौनों और किन्नरों को भी 300 रूपये प्रति माह पेंशन दी गई है। विधवा बहनों की पेंशन राशि 300 रूपये प्रति मास से बढ़ाकर 350 रूपये प्रति माह कर दी गई है। इसके साथ-साथ भातप्रति हज़ार विकलांगों और नेत्रहीनों की पेंशन

राशि 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह की है। नम्बरदारों और चौकीदारों का मानदेय 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। नगर पालिकाओं, नगर परिशदों, पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिशदों के सभी नुमाइंदों का पहली बार एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति माह किया गया है। 91 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया है जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 175 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तीन वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 481.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। भाहरी क्षेत्र में गृहकार के बारे में ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है। पिछली सरकार के समय में इस बारे में आन्दोलन हुआ था, उस समय में विपक्ष में था और पार्टी अध्यक्ष भी था तब मैंने कहा था कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम इस पॉलिसी के बारे में जो ओल्ड पॉलिसी होगी उसके मुताबिक विचार करेंगे। लेकिन हमने आते ही पूरा का पूरा गृहकार ही माफ कर दिया। इसके अतिरिक्त चूल्हा टैक्स को माफ करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 152 गांवों में 40 करोड़ रुपये की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण किया है ताकि गांवों में जो पोटेंशियल है वह आगे विकास करे, तरक्की करे। खेलों के मामले में प्रगति हो। बच्चों के पोशाहार की दर दो रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन से बढ़ाकर तीन रुपये की गई है माताओं के लिए यह पोशाहार की राशि 2.5 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति दिन की गई है। यह पूरे देश में सबसे

अधिक है। मेरी सरकार को हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का आ निर्वाद और सहयोग सही मायनों में चाहिए। मैं इस महान योगदान के लिए सभी सदस्यों का समर्पित मांगता हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो यहीं अभिभाषण दिया और पूरे प्रदेश में भारी विकास कार्य हुए हैं उनका यहां चित्रण किया और सरकार के बारे में जो विजन दिया है, उसका आइना दिया है। उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से और प्रदेश के लोगों की तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में मैं एक ही बात कहता हूँ -

“जिन्दगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है,

हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है,

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने,

आगे सारा आसमान अभी बाकी है।”

यह हमारा संकल्प भी है, हमारा रास्ता भी है।
बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

Mr. Speaker : Question is

That an address be presented to the Governmer in the following terms :-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the governor

for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 7th March, 2008 at 2.00 P.M.”

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon’ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 18th March, 2008.

16.40 Hrs.

(The Sabha than *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 18th March, 2008).